केंद्र और राज्य शासन से विज्ञापन के लिए अनुमोदित
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक
17 वर्षों से निरंतर....
Website:- www.malwaherald.com
RNI No. MPHIN/2010/33238
dainikmalwaherald@yahoo.com
malwaherald@gmail.com

महाकालेश्वर जी का संध्या काल आरती श्रृंगार दर्शन

मालवा हेराल्ड

सुविचार

दुःख का कारण कर्म का अभाव, सुख का कारण कर्म का प्रभाव और शांति का कारण स्वयं का स्वभाव है...

वर्ष : 17 अंक : 38 | उज्जैन, शनिवार 18 जुलाई 2026 | पृष्ठ-8 मूल्य-1 रुपए

न्यूज ब्रीफ

क्कमें नहीं होंगे तीन सीट पर विधानसभा के उपचुनाव, निर्वाचन आयुक्त का छह महीने ही समय होने का हवाला

लखनऊ/ जीएनएस। उत्तर प्रदेश के घोसी, दुद्धी और फरीदपुर में विधानसभा उप चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टियों को निर्वाचन आयोग ने बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सिर्फ छह महीने के समय ही बाकी देश निर्वाचन आयोग ने यहां की तीन विधानसभा सीट पर उप चुनाव न कराने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश की घोसी, दुद्धी और फरीदपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नहीं होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के आम चुनाव में एक वर्ष से कम समय बचा है, इसलिए इन तीनों रिक्त सीटों पर अब उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में एक वर्ष से भी कम समय बचा है, इसलिए यहां की तीन सीटों पर उपचुनाव कराने का फैसला नहीं लिया गया है। भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान में आयोजित राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन में ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया दस अप्रैल तक चली। इसके बाद पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के चुनाव हुए, जिससे निर्वाचन आयोग लगातार चुनावी कार्यों में व्यस्त रहा। उन्होंने बताया कि अब आयोग के पास कुछ समय है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक साल से कम समय शेष है, इसलिए घोसी, दुद्धी और फरीदपुर सीटों पर उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव संविधान के अनुसार होता है, संविधान में ऑनलाइन चुनाव का प्रावधान नहीं है इसलिए देश में ऑनलाइन चुनाव कराने का कोई विचार फिलहाल नहीं है।

यूपी के लिए चिराग का पंडित-पासी-पासवान फॉर्मूला, 403 सीटों पर नजर; पंजाब में भी होगी LJPR की एंट्री

हाजीपुर/ जीएनएस। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी विस्तार की सोच के साथ अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हाजीपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर मजबूती से तैयारी कर रही है। चिराग पासवान ने कहा कि हम समावेश की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जब मैं बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और 14 करोड़ बिहारी की बात करता हूं, तो विपक्ष के कुछ दल आपको जातियों में बांटकर और पीडीए की बात करके अलग-अलग वर्ग और समुदाय में बांटने का काम करते हैं। हमारी सोच ए टू जेड को साथ लेकर चलने की है। उन्होंने कहा कि समाज में यह मानसिकता बनाई गई है कि एक समाज पंक्ति में सबसे ऊपर है और एक सबसे हाशिए पर। अनुसूचित जाति के साथ आज भी कई जगह भेदभाव और उत्पीड़न के उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन सिर्फ एक वर्ग ही नहीं, ऊंची जाति के लोग भी उत्पीड़न के शिकार होते हैं। चिराग ने कहा कि बिहार में तिवारी जी (भरत तिवारी) की हत्या और एनकाउंटर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि असामाजिक सोच के कारण समाज का हर वर्ग कहीं न कहीं पीड़ित होता है। इसी सोच के तहत उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए पंडित-पासी-पासवान का फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा, यह वह ब्रैकेट है जिसके बीच हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय शामिल है। सबका समावेश होता है। चिराग पासवान ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अलावा पार्टी पंजाब और उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वे परसों पंजाब जाएंगे और स्वर्ण मंदिर में माथा टेककर विधिवत चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। अगले हफ्ते उत्तराखंड में भी राज्य इकाई ने चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है।

टीकमगढ़ में बनेगा सर्व सुविधायुक्त मेडिकल कॉलेज : मुख्यमंत्री

बुंदेलखंड के किसानों ने पानी का अभाव झेला, गरीबी झेली, अब केन-बेतवा नदी जोड़ो से हम इसे बनाएंगे समृद्ध

भोपाल/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है। बुंदेलखंड एक नए निवेश केंद्र के रूप में उभर रहा है। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य इस क्षेत्र की प्रगति को नई गति दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड अब बदल रहा है। बुंदेलखंड के किसानों ने पानी के अभाव में गरीबी झेली और कई कठिनाइयां उठाईं। रोजगार की भारी कमी का दंश भी झेला। लेकिन अब हम केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के जरिए बुंदेलखंड को समृद्ध बनाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना पूरी होने पर यह क्षेत्र खेती के मामले में पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस विशाल परियोजना से टीकमगढ़ जिले की हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी, जिससे किसानों के खेतों में पर्याप्त पानी पहुंचेगा और उनकी आय में ऐतिहासिक वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ जिले को 189 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 72 विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 102.45 करोड़ रूपए के 33 कामों का लोकार्पण और 86.66 करोड़ रुपए के 39 कामों का भूमिपूजन शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिले के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि टीकमगढ़ में सर्वसुविधायुक्त भव्य मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इसका भूमिपूजन भी शीघ्र ही किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न शासकीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज टीकमगढ़ जिले को अमृत भारत रेलवे स्टेशन की बड़ी सुविधा मिली है। इसके साथ-साथ जतारा और बड़ागांव धसान में सर्वसुविधायुक्त सांदीपनि विद्यालय भवनों और सोलह विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के नव-निर्माण कार्यों का उपहार भी मिला है। इतना ही नहीं, हमारे युवाओं और खिलाड़ियों के लिए हॉकी सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम और बास्केटबॉल कोर्ट का भी लोकार्पण हुआ है। खरगापुर में 40 करोड़ रूपए से बनने वाले नए सांदीपनि विद्यालय भवन का भूमिपूजन भी आज हो गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बदलते समय की जरूरतों के मुताबिक प्रदेश के बच्चों को सांदीपनि विद्यालयों के जरिए संस्कारों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। हमारे ये विद्यालय भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की अमर मित्रता के पर्याय बने हैं। भविष्य में युवा पीढ़ी को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए जैसे विद्यालय चाहिए, आज उन्हें वैसे ही विद्यालय उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2002-03 तक सिंचाई का रकबा मात्र 7.50 लाख हेक्टेयर था। हमारी सरकार में प्रदेश की सिंचित भूमि का रकबा बढ़कर अब 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। हम एक करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार लाड़ली बहनों को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर सौगात दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश विवाह, तलाक और वसीयत के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के सभी देवस्थानों को भव्य स्वरूप में विकसित कर रही है। समान भाव से कार्य करते हुए सभी धर्मों, सभी समाज के लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत अगर रानी को हर माह 1500 रुपए मिल रहे हैं तो रुखसाना को भी इस योजना का पूरा लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में राज्य सरकार किसानों की समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना और अन्य योजनाओं के जरिए पशुपालकों को अनुदान और अन्य मदद भी दी जा रही है। गौशाला खोलने पर प्रति गौमाता 40 रुपए की आर्थिक/अनुदान सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को उत्पादित दूध का समुचित दाम भी मिलने लगा है। हमारे मछुआरें भाई-बहनों की समृद्धि के लिए राज्य सरकार मत्स्य उत्पादन को भी प्रोत्साहित कर रही है।

4 साल की बच्ची की मौत पर 6 साल बाद माता-पिता को 40.37 लाख का मुआवजा, ट्रिब्यूनल ने ड्राइवर को ठहराया दोषी

नई दिल्ली/ जीएनएस। दिल्ली के एक मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 4 वर्षीय बच्ची की 2020 में तेज रफ्तार कार की टक्कर में मौत के मामले में उसके माता-पिता को 40.37 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

रेस इप्सा लोकीटुर का दिया हवाला- ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि दुर्घटना बिना बीमा वाली कार की लापरवाही और तेज रफ्तार से ड्राइविंग के कारण हुई। ट्रिब्यूनल ने ड्राइवर और कार मालिक को संयुक्त रूप से मुआवजा चुकाने का निर्देश दिया है। 16 जुलाई को दिए गए आदेश में ट्रिब्यूनल ने रेस इप्सा लोकीटुर के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि साबित हो गया है कि दुर्घटना ड्राइवर की लापरवाही से हुई थी।

12 अक्टूबर 2020 को उत्तर दिल्ली में बच्ची अपने भाई-बहनों और एक अन्य व्यक्ति के साथ सड़क पार कर रही थी। तेज रफ्तार से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। बच्ची को गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मौत हो गई।

मेडिकल फील्ड में लड़कों से ज्यादा लड़कियों की दिलचस्पी, NEET में हिंदी मीडियम वालों की क्या है स्थिति?

नई दिल्ली/ जीएनएस। युवाओं में मेडिकल से जुड़े कोर्सों में दाखिले का क्रेज न सिर्फ बना हुआ है बल्कि इसमें लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है।

इसका अंदाजा मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की एक ताजा रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसके मुताबिक पिछले आठ सालों में मेडिकल में दाखिले के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में पचास प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसमें भी पुरुषों की तुलना में बेटियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है।

मेडिकल फील्ड में लड़कियों की दिलचस्पी- रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में मेडिकल में दाखिले से जुड़े परीक्षा नीट-यूजी के लिए आवेदन करने वालों की संख्या जहां 15 लाख थी, वहीं 2026 में आवेदन करने वालों की संख्या 22.79 लाख हो गई है। यानी पिछले आठ सालों में इसमें साढ़े सात लाख से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो 2019 के मुकाबले पचास प्रतिशत अधिक है।

वहीं 2019 में जहां आवेदन करने वालों में 6.80 लाख पुरुष व 8.38 लाख बेटियां आवेदन थी, जबकि 2026 में इनमें आवेदन करने वालों में पुरुषों की संख्या 9.46 लाख हो गई, जबकि बेटियां की संख्या 13.32 लाख हो गई है।

आंकड़ों को देखें तो पिछले आठ सालों में नीट-यूजी में आवेदन करने वालों में पुरुषों की संख्या में जहां 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, वहीं बेटियों की संख्या में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

अरुणाचल में बाढ़ की कहर से टूटीं सड़कें, हाथी कैसे बना लाइफलाइन?

ईटानगर/ जीएनएस। हाल ही में अचानक आई बाढ़ ने अरुणाचल प्रदेश के निचले सियांग जिले के नारी-कोयू निर्वाचन क्षेत्र के पूरे सड़क नेटवर्क को तबाह कर दिया है। सड़कें और पुल बह जाने के कारण कोयू सर्कल के अंतर्गत आने वाले गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। आज भी 12 से अधिक गांव बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं, क्योंकि मुख्य मार्गों की मरम्मत अब तक नहीं हो पाई है।

इन विकट परिस्थितियों में प्रशासन ने स्थानीय ग्रामीणों के सक्रिय समर्थन के साथ राहत सामग्री, ईंधन और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए हाथियों का रुख किया है। हालांकि, यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। इन सौम्य दिग्गजों को खड़ी पहाड़ियों, उफनती नदियों और मीलों लंबे पथरीले रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है।

इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद, वे अपनी पीठ पर भारी वजन ढोकर उन जगहों तक पहुंच रहे हैं, जहां सड़क मार्ग से जाना अब असंभव है। राज्य के इस सबसे मुश्किल दौर में, उनका यह मूक लेकिन महत्वपूर्ण योगदान सैकड़ों बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए किसी जीवनरेखा से कम नहीं है और प्रकृति के कहर के बीच एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है।

अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने, भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ को लगभग तीन सप्ताह बीत चुके हैं। इस आपदा ने इस सीमावर्ती राज्य के कई हिस्सों को बुरी तरह पस्त कर दिया है और लोग अब भी सामान्य जीवन की ओर लौटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

SIR में नाम कटने पर नागरिकता नहीं जाती, सुप्रीम कोर्ट ने EC और बंगाल सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली/ जीएनएस। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को चुनाव आयोग, पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग से एक PIL पर जवाब मांगा है।

इस PIL में SIR प्रक्रिया के दौरान हटाए गए वोटरों की ओर से दायर दावों और आपत्तियों का विधानसभा क्षेत्र-वार डेटा सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब- सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की SIR कमेटी के चेयरमैन प्रसेनजीत बोस ने दायर की थी। इस याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने सुनवाई की।

वकील नेहा राठी की दायर याचिका में पश्चिम बंगाल स्पेशल इंटेंसिव रिविजन प्रक्रिया से जुड़ा विधानसभा क्षेत्र-वार डेटा मांगा। इसमें फॉर्म 6 और 7 की संख्या (दायर, स्वीकार और खारिज) और अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने अपील के लंबित रहने और उनके निपटारे की जानकारी शामिल थी।

बोस की ओर से पेश सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि हटाए गए वोटरों के दावों और आपत्तियों को देखने के लिए बनाए गए 18 ट्रिब्यूनल जिस तरह से काम कर रहे हैं, उससे व्यावहारिक स्तर पर गड़बड़ियां और देरी हो रही है।

बेंच ने बिहार SIR मामले में दिए गए फैसले का जिक्र करते हुए कहा, चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि जब कोई ट्रिब्यूनल यह कहे कि कोई व्यक्ति SIR लिस्ट में नहीं हो सकता, तो EC को नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता तय करने के लिए मामले को केंद्रीय मंत्रालय को भेजना होगा।

अब ऐसी दिखेगी दिल्ली! खुली मिट्टी पर उगेगी हरियाली, प्रदूषण रोकने के लिए बनेगा ब्लू-ग्रीन कॉरिडोर

नई दिल्ली/ जीएनएस। प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए शहरी योजनाकार, नीति निर्माता और पर्यावरण विशेषज्ञ ब्लू-ग्रीन शहरी आधारभूत ढांचा के निर्माण पर बल दे रहे हैं।

पर्यावरण-अनुकूल विकास और जलवायु परिवर्तन के परिणाम को कम करने के लिए यह एक ऐसी आधुनिक शहरी नियोजन प्रणाली है, जिसमें जल निकायों (ब्लू) और हरियाली (ग्रीन) को सीमेंट-कंक्रीट की इमारतों के साथ एकीकृत किया जाता है।

क्लीन एयर डायलॉग्स में उन्होंने वृक्षारोपण के साथ ही पारिस्थितिक आधारभूत ढांचे के विभिन्न घटकों आर्द्रभूमि, जंगल, वन्यजीव अभयारण्य, सड़कें और पार्क बढ़ाने और एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। कहा, धूल पैदा करने वाली खुली मिट्टी को स्थायी रूप से सक्रिय ग्रीन-ब्लू गलियारों से बदलने की तत्काल आवश्यकता है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के रिसोर्स लैब द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में क्लीन एयर डायलाग्स का तीसरा सत्र आयोजित किया गया। इसमें सीएक्यूएम के सदस्य (तकनीकी) डॉ. एसडी अत्री ने कहा कि एनसीआर के शहरों में सड़क पुनर्विकास में एंड-टू-एंड पेविंग या हरितीकरण को अनिवार्य किया गया है।

दिल्ली सरकार के पर्यावरण/शहरी विकास के सचिव और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष विजय कुमार बिधूड़ी ने कहा कि पर्यावरणनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का विस्तार दीर्घकालिक समाधान है। दिल्ली 13 हजार नई इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा स्थापित कर रहा है।

कट्टर बेईमान; PM मोदी ने कानून-व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी पर बोला हमला

नई दिल्ली/ जीएनएस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर कानून-व्यवस्था और कई अन्य मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ सरकार को कट्टर बेईमान करार देते हुए कहा कि इसकी न तो साफ नीयत है और न ही ईमानदारी है। जालंधर में 5,470 करोड़ रुपये की लागत वाली रेलवे और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है।

उन्होंने कहा कि यहां कोई नहीं जानता कि कब और कहां गैंगवार हो जाए या किस दिशा से गोलियां चलने लगें। पीएम मोदी ने कहा, खुलेआम रंगदारी मांगी जा रही हैं और यहां तक कि पुलिस थानों पर हमले की घटनाएं भी आम हो गई हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब के नाम पर कर्ज लिया जा रहा है और बजट का एक बड़ा हिस्सा उस कर्ज को चुकाने में खर्च हो रहा है, जबकि राज्य सरकार चलाने वाले लोग उसी पैसे का लाभ उठा रहे हैं।

पीएम मोदी ने शिरोमणि अकाली दल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उसे जनता की चिंता नहीं है, क्योंकि वह अपने ही मामलों में उलझा हुआ है। उन्होंने कहा, पूरे पंजाब में विकास कार्य ठप हो गए हैं। जिन परियोजनाओं को दिखाया जा रहा है, वे सभी केंद्र सरकार की पहल हैं। प्रधानमंत्री ने यहां शुरू की गई विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा, अब जालंधर विकास का गवाह बन रहा है।

पीएम मोदी ने कहा कि भले ही पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन केंद्र में भाजपा नीत राजग सरकार राज्य के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, 2014 से पहले रेलवे की क्या स्थिति थी? उस समय की कांग्रेस सरकार नई ट्रेनों को लेकर झूठी घोषणाएं करती थी और फिर चुप बैठ जाती थी। मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की पंजाब इकाई में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अंदरूनी लड़ाई कभी खत्म होती नजर नहीं आती। उन्होंने कहा, वे जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वे आपस में ही लड़ रहे हैं।

बिजलपुर रोड निर्माण में देरी पर निगम आयुक्त सख्त, एजेंसी को टर्मिनेशन नोटिस जारी करने के निर्देश

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने शुक्रवार को शहर में मास्टर प्लान के तहत निर्माणाधीन सड़कों और मल्टीलेवल पार्किंग परियोजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बिजलपुर रोड निर्माण कार्य की बेहद धीमी प्रगति पर उन्होंने संबंधित निर्माण एजेंसी पर गहरी नाराजगी जताते हुए प्रतिदिन पेनल्टी लगाने और टर्मिनेशन नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं तिलक नगर क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य की गति बढ़ाकर एक माह के भीतर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

आयुक्त ने ग्रेटर कैलाश रोड पर निर्माणाधीन मल्टीलेवल पार्किंग का भी निरीक्षण किया और शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। निगम के अनुसार इस पार्किंग में लगभग 150 चार पहिया और 150 से अधिक दोपहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी।

बिजलपुर क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान सड़क निर्माण की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर आयुक्त ने निर्माण एजेंसी के.एन. नारंग के खिलाफ कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को एजेंसी पर प्रतिदिन आर्थिक दंड लगाने और अनुबंध समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

तिलक नगर में निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने संबंधित एजेंसी इंजीनियरिंग इनोवेशन एंड कंपनी को भी कार्य में लापरवाही पर फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य की गति बढ़ाकर इसे एक माह के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए।

निरीक्षण के दौरान खड़ा गणपति से स्कीम-155 टिगरिया बादशाह तक प्रस्तावित सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं की भी समीक्षा की गई। आयुक्त ने 15वीं बटालियन के पास सड़क निर्माण के लिए आवश्यक भूमि संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाने, बाधक वृक्षों का नियमानुसार ट्रांसप्लांट या हटाने तथा फेंसिंग का कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन भवन स्वामियों ने अतिक्रमण का कुछ हिस्सा स्वयं हटा लिया है, उन्हें शेष बाधक हिस्से को भी निर्धारित सीमा तक हटाने के लिए कहा जाए, ताकि निगम की कार्रवाई के दौरान अनावश्यक नुकसान से बचा जा सके।

संगम जीटीएस के सामने निर्माणाधीन पुलिया का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने संबंधित एजेंसी को एक माह के भीतर पुलिया का कार्य स्लैब लेवल तक पूरा करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर, कार्यपालन यंत्री पी.एस. कुशवाह, सहायक यंत्री नरेश जायसवाल, उपयंत्री पराग अग्रवाल, संबंधित कंसल्टेंट, निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि तथा नगर निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि शहर के विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करना सभी एजेंसियों की जिम्मेदारी है।

इंदौर आबकारी विभाग द्वारा नशे के विरूद्ध कार्रवाई

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी के द्वारा दिये निर्देशानुसार इंदौर जिले में अवैध मदिरा के विरूद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई जारी है। वृत महू (ब) प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री पवन टिकेकर एवं उनके दल द्वारा गत दिवस गश्त के दौरान शंका के आधार पर महू पीथमपुर रोड पर बिना नंबर का दो पहिया वाहन हीरो स्प्लेंडर को रोक कर तलाशी लेने पर देशी प्लेन मदिरा के 50 पाव बरामद किये गये, जो अवैध रूप से परिवहन कर ले जाये जा रही थी। उक्त मदिरा तथा वाहन को विधिवत् रूप से जप्त कर कब्जे में लिया गया। आरोपी हरिओम पिता पुरुषोत्तम रजक निवासी पीथमपुर के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा 34(1)क के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उक्त मदिरा और वाहन का कुल बाजार मूल्य 13 हजार 500 रुपये है।

मध्यप्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी घर बैठे देख सकेंगे GPF स्टेटमेंट, ऑनलाइन शिकायत निवारण की भी सुविधा

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्यप्रदेश, ग्वालियर ने राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों का वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक लेखा विवरण अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। इससे अभिदाता अब घर बैठे अपने GPF खाते का वार्षिक विवरण देख एवं डाउनलोड कर सकेंगे। कार्यालय महालेखाकार के अनुसार अभिदाता www.agmp.nic.in पर जाकर अपनी संबंधित सीरीज, सामान्य भविष्य निधि (GPF) लेखा क्रमांक तथा पासवर्ड दर्ज कर वार्षिक लेखा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। यदि वार्षिक लेखा विवरण में किसी प्रकार की विसंगति अथवा त्रुटि पाई जाती है, तो उसके ऑनलाइन सुधार के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध Accountant General (A&E) के अंतर्गत Online Service में जाकर Register Grievances (AG) विकल्प के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है। कार्यालय द्वारा इन शिकायतों का निराकरण महालेखाकार की निगरानी में सामान्यतः एक माह के भीतर किया जाता है। सामान्य भविष्य निधि से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, विभिन्न आवेदन प्रारूप तथा अन्य आवश्यक प्रपत्र भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिससे अभिदाताओं को आवश्यक जानकारी एवं सेवाएं एक ही मंच पर प्राप्त हो सकें। अभिदाता अपनी शिकायत दूरभाष 0751-2432457 तथा व्हाट्सएप नंबर +91-8827409410 पर भी दर्ज करा सकते हैं।

इंदौर में रेत मंडी की बिजली ग्रिड का नहीं निकल रहा मुहूर्त

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। आईडीए की स्कीम 97 यानी रेत मंडी के पास बन रही उच्चदाब 132 केवी बिजली ग्रिड के भूमिपूजन का मुहूर्त दो साल बाद भी नहीं निकला पा रहा है।

पहले ग्रिड के लिए जमीन नहीं मिल रही थी। फिर जमीन कम पड़ गई। अतिरिक्त जमीन आवंटन हुआ तो नामांतरण को लेकर परेशानी आई। अब जमीन की सारी कागजी औपचारिकता पूरी हो गई तो भी ग्रिड निर्माण का काम शुरू नहीं हो सका। अब राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र (कैट) और बिजली ट्रांसमिशन कंपनी के बीच सहमति बनने तक ग्रिड का काम शुरू नहीं हो सकेगा।

प्रदेश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहर इंदौर में विद्युत अधोसंरचना को मजबूती देने के लिए शहर के दूसरे हिस्से में 132 केवी का बिजली सब स्टेशन बनाया जाना है। करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस सब स्टेशन से शहर के राजेंद्रनगर से लेकर पूरे राऊ, बायपास क्षेत्र व दक्षिण और पश्चिमी सिरे की बसाहट को बेहतर बिजली सुविधा मिल सकेगी। इंदौर में लगातार बढ़ रहे विद्युत भार को देखते हुए इस उपकेंद्र की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। उपकेंद्र के निर्माण से लोड बैलेंसिंग बेहतर होगी, वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार आएगा तथा किसी फॉल्ट या आपात स्थिति में वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना आसान होगा। इससे लाखों घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

पर्पल फेयर इंदौर-2026 में सांसद श्री लालवानी ने दिव्यांग प्रतिभाओं का किया सम्मान

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर) सीहोर तथा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को रवींद्र नाट्य गृह में ÷पर्पल फेयर इंदौर-2026÷ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया तथा उन्हें अपनी प्रेरक जीवन यात्रा साझा करने का अवसर मिला। दिव्यांग बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उपस्थितजनों का मन मोह लिया।

सांसद श्री शंकर लालवानी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए लगातार संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही हैं। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक दिव्यांगजनों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि इंदौर दिव्यांगजनों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और यहां राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अनेक एनजीओ सक्रिय हैं।

सांसद श्री लालवानी ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर) के इंदौर में सैटेलाइट सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इससे इंदौर सहित संभाग के अन्य जिलों के भी दिव्यांगजन और संस्थाएं लाभान्वित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नई दिव्यांग नीति तैयार करते समय इंदौर के अनुभवी स्वयंसेवी संगठनों से भी सुझाव लिए जाएं ताकि नीति अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बन सके। उन्होंने इंदौर की कई प्रेरणादायी दिव्यांग प्रतिभाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इंदौर में अनेक युवाओं ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से नई पहचान बनाई है। उन्होंने इन सफलताओं का श्रेय सेवा भाव से कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों और समाज के सहयोग को दिया।

कार्यक्रम में विधायक श्री गोलू शुक्ला भी शामिल हुए और दिव्यांग बच्चों से संवाद करते हुए उनका हौसला बढ़ाया।

निशक्तजन आयुक्त डॉ. अजय खेमरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए नई समावेशी दिव्यांग नीति तैयार की जा रही है। इस नीति के निर्माण में विशेषज्ञों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सभी संबंधित पक्षों के सुझाव शामिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों की मदद के लिए 32 करोड़ रुपये की

दिव्यांग निधि स्थापित की है। इस निधि से प्रतिभावान दिव्यांगजनों को खेल, उच्च शिक्षा, कला, संस्कृति आदि क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में भी मदद दी जाएगी। युवाओं को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। स्टार्टअप में भी मदद की जाएगी।

कार्यक्रम के प्रारंभ में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर) सीहोर के डायरेक्टर श्री अखिलेश कुमार शुक्ला ने अतिथियों का स्वागत करते हुए पर्पल फेयर के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह आयोजन दिव्यांगजनों की प्रतिभा, आत्मविश्वास और समाज में उनकी सहभागिता को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मंच है।

कार्यक्रम में दिव्यांग प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ प्रेरणादायी अनुभव साझा किए गए। दोपहर बाद भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। अंत में आभार प्रदर्शन के साथ पर्पल फेयर इंदौर-2026 का समापन हुआ।

शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय इंदौर में विश्व युवा कौशल दिवस पर करियर मार्गदर्शन एवं व्यक्तित्व विकास विषयक व्याख्यान आयोजित

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय इंदौर में प्राचार्य डॉ. वी. डी. श्रीवास्तव के संरक्षण तथा प्रशासनिक अधिकारी डॉ. वी. पी. बैरागी के मार्गदर्शन में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर छात्राओं के लिए करियर मार्गदर्शन एवं व्यक्तित्व विकास विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया।

मुख्य वक्ता डॉ. शैलेन्द्र पिपरिया ने छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की प्रभावी रणनीति पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। उन्होंने UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन, नियमित अध्ययन, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, उत्तर लेखन कौशल तथा निरंतर अभ्यास के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सफलता का मूलमंत्र धैर्य, अनुशासन, सतत सीखने की प्रवृत्ति और व्यवहारिक ज्ञान है। साथ ही छात्राओं को रोजगार के बदलते अवसरों, कौशल विकास तथा व्यक्तित्व निर्माण के माध्यम से प्रतिस्पर्धी वातावरण में स्वयं को सक्षम बनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की द्वितीय मुख्य वक्ता सुश्री रागिनी सिंह ठाकुर (निर्माण फाउंडेशन) ने छात्राओं को तकनीकी एवं व्यावहारिक कौशल विकसित करने, आत्मनिर्भर बनने तथा समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रो. निधि गुप्ता ने किया तथा आभार प्रदर्शन करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की नोडल अधिकारी डॉ. सीमा तिवारी ने किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में कार्यक्रम प्रभारी प्रो. ऋतु मथुरिया, समिति सदस्य डॉ. शीतल झा, डॉ. प्रियंका जैन एवं डॉ. अंजना चारसिया का विशेष सहयोग रहा।

इंदौर में घर निर्माण की मशीनों के शहर में प्रवेश पर रोक से अपना आशियाना बनवाने को लेकर रहवासी हो रहे परेशान

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर के बड़ा गणपति सड़क पर बेकाबू ट्रक से हुए हादसे को 11 महीनों बीत चुके हैं। घटना कई परिवारों के लिए दुस्वप्न की तरह रही, लेकिन जिम्मेदारों ने व्यवस्था सुधारने के बजाए ऐसा लाइसेंसी सिस्टम बना दिया कि अब अपने सपनों का घर बनाने का शहरवासियों का सपना रोज टूट रहा है।

15 सितंबर 2025 को एरोड्रम क्षेत्र में शिक्षक नगर से बड़ा गणपति तक शराबी ट्रक चालक मौत बनकर दौड़ा था। ट्रक ने दोपहिया-चार पहिया सहित एक दर्जन से ज्यादा वाहनों को टक्कर मार दी थी। हादसे में दो की मौके पर मौत के साथ 14 लोग घायल व एक युवती गंभीर घायल हो गई थी।

हादसे के बाद शहर की सीमाओं पर यातायात के जवान मुस्तैद रहते हैं, लेकिन बीते साल नो-एंट्री में बड़ा गणपति क्षेत्र में एक बेकाबू ट्रक को प्रवेश मिला था। गलती ट्रक को प्रवेश देने वालों की थी, लेकिन सजा बेकसूर वाहन चालकों को भुगतनी पड़ी। घटना से उम्मीद थी कि यातायात की निगरानी व्यवस्था दुरुस्त होगी, लेकिन हुआ कुछ और ही।

अपने आशियाने का सपना देखने वाले असहाय हैं- नियमों के फेर में अपने आशियाने का सपना देखने वाले उलझकर असहाय हैं।

महापौर और विधायक ने मधु मिलन-छावनी मास्टर प्लान रोड का किया निरीक्षण, सुरक्षा और गुणवत्ता पर दिया जोर

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर में यातायात व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाने के लिए नगर निगम द्वारा किए जा रहे मास्टर प्लान सड़क निर्माण कार्यों के तहत महापौर पुष्यमित्र भार्गव और विधायक गोलू शुक्ला ने शुक्रवार को मधु मिलन चौराहे से छावनी चौराहे तक निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान जनकार्य प्रभारी राजेंद्र राठौर, पार्षद पंखुड़ी जैन, अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर, अधीक्षण यंत्री पी.एस. कुशवाह, सहायक यंत्री नरेश जायसवाल, महापौर प्रतिनिधि भावेश दवे सहित अन्य जनप्रतिनिधि और निगम अधिकारी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि सड़क निर्माण शुरू होने के समय वर्षा ऋतु को लेकर कई लोगों को आशंका थी कि नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन स्थानीय रहवासियों से चर्चा के दौरान यह सामने आया कि नगर निगम द्वारा बेहतर समन्वय और तेज गति से किए जा रहे कार्यों से लोग संतुष्ट हैं। उन्होंने निगम की कार्यशैली की सराहना करने पर नागरिकों का आभार भी व्यक्त किया।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (एसीएस) परीक्षा - 2026 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े के निर्देशन में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (एसीएस) परीक्षा - 2026 को लेकर उपायुक्त (राजस्व) श्रीमती सपना लोवंशी ने संभागायुक्त कार्यालय में समीक्षा बैठक ली। बैठक में बताया गया कि आयोग द्वारा आयोजित सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (एसीएस) परीक्षा 19 जुलाई रविवार को इंदौर के 6 केन्द्रों पर सम्पन्न होगी। इस परीक्षा में कुल 2 हजार 398 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उक्त परीक्षा के लिए संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े को परीक्षा समन्वयक बनाया गया है एवं उपायुक्त (राजस्व) श्रीमती सपना लोवंशी को परीक्षा प्रभारी बनाया गया है। बैठक में संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली के पर्यवेक्षक श्री जितेन्द्र शर्मा, पोस्ट मास्टर जनरल श्री अजय बाफना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी, प्राध्यापक डॉ. डी.के. गुप्ता, बिजली विभाग के अधिकारी श्री अनुज गुप्ता, स्थानीय निरीक्षण अधिकारी, केन्द्राध्यक्ष, पुलिस विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में परीक्षा प्रभारी ने बताया कि सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (एसीएस) परीक्षा 19 जुलाई को दो सत्रों में आयोजित होगी।

'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' अभियान के बीच इंदौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन तस्कर गिरफ्तार

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चलाए जा रहे नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान के तहत जनजागरूकता के साथ-साथ नशे के कारोबारियों के खिलाफ भी लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच और परदेशीपुरा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 27 लाख नहीं, बल्कि लगभग 2.70 लाख रुपये मूल्य के 13.2 ग्राम ब्राउन शुगर और 13.94 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है।

पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस लगातार मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है। कार्रवाई के दौरान क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर आजाद नगर निवासी शाहरुख रऊफ (26) को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से करीब 13.94 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.40 लाख रुपये है।

क्राइम ब्रांच ने एनडीपीएस एक्ट के एक अन्य मामले में लंबे समय से फरार चल रहे भूरा उर्फ औहिल उर्फ शूटर (23) निवासी गांधीनगर, उज्जैन को भी गिरफ्तार किया। पुलिस उससे पूछताछ कर उसके नेटवर्क और अन्य तस्करों के बारे में जानकारी जुटा रही है।

वहीं परदेशीपुरा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मयूर तांबारे, निवासी बंशी प्रेस की चाल, परदेशीपुरा को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 13.2 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.30 लाख रुपये बताई गई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

इंदौर पुलिस का कहना है कि नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान के तहत एक ओर लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई भी जारी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे अपराधियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान को मिला नया अंदाज़, गीत और शॉर्ट फिल्म से दिया जाएगा नशामुक्ति का संदेश

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा संचालित नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान के तहत नशे के खिलाफ जनजागरूकता को नया आयाम देते हुए विशेष जागरूकता गीत और शॉर्ट फिल्म का लोकार्पण किया गया। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने शुक्रवार को इन दोनों वीडियो का विमोचन करते हुए आमजन से नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की।

अभियान के अंतर्गत पुलिस उपायुक्त (क्राइम) राजेश कुमार त्रिपाठी द्वारा गाया गया जागरूकता गीत भैया, नशे से दूरी है ज़रूरीज जीवन की हर खुशियां हैं ज़रूरी लोगों को नशे के दुष्परिणामों से सावधान करते हुए स्वस्थ और सकारात्मक जीवन का संदेश देता है। वहीं नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित शॉर्ट फिल्म में यह दर्शाया गया है कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य और भविष्य को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

इंदौर पुलिस इन जागरूकता वीडियो को शहर में संचालित जनजागरूकता रथों, प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और विभिन्न एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रसारित करेगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक नशे से दूरी है ज़रूरी का संदेश पहुंचाया जा सके।

पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने कहा कि इंदौर पुलिस नशे के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार नवाचार कर रही है। समाज के हर वर्ग और हर आयु के लोगों तक पहुंचकर उन्हें नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और अपने परिवार, मित्रों तथा आसपास के लोगों को भी नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करें।

इंदौर पुलिस ने नागरिकों से यह भी आग्रह किया कि यदि कहीं अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी या नशे से जुड़ी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत क्राइम वॉच हेल्पलाइन 7019108283 पर दें। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

अभियान के तहत पेंटिंग, रंगोली, स्लोगन, कविता, निबंध लेखन और ओपन माइक जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं और आम नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में जनआंदोलन तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। इंदौर पुलिस का कहना है कि जनसहभागिता ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है और इसी के माध्यम से नशे के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ी जा सकती है।

फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन में संभावित फर्जीवाड़े की आशंका, एक छात्र का भविष्य दांव पर

एम.पी. फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। एक गंभीर प्रशासनिक अनियमितता अथवा संभावित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसने न केवल एक योग्य फार्मेसी छात्र के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है, बल्कि प्रदेश की ड्रग लाइसेंस प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एम.पी. फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ड्रग इंस्पेक्टर श्रीमती पूजा भाभर को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि यदि यह मामला तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि फर्जीवाड़े का है, तो इसके दोषियों पर कठोर वैधानिक कार्रवाई होना आवश्यक है।

जिलाध्यक्ष मिथुन वप्ता ने बताया कि मंदसौर निवासी मुकेश पाटीदार (फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन क्रमांक 86360) ने वर्ष 2023 में बी.फार्मेसी उत्तीर्ण की तथा वर्ष 2025 में मध्यप्रदेश फार्मेसी काउंसिल से विधिवत पंजीयन प्राप्त किया। लेकिन जब उन्होंने अपना पहला ड्रग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, तो पोर्टल पर ऑलरेडी एक्जिट इन अनादर लाइसेंस का संदेश प्रदर्शित हुआ। सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि जिस अभ्यर्थी ने आज तक कभी किसी ड्रग लाइसेंस के लिए आवेदन ही नहीं किया, उसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक किसी अन्य लाइसेंस से कैसे जुड़ गया? यदि रजिस्ट्रेशन क्रमांक 86360 वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति के ड्रग लाइसेंस में उपयोग किया गया है, तो यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि वह ड्रग लाइसेंस किसके नाम पर जारी हुआ।आवेदन के समय फार्मासिस्ट के पंजीयन का सत्यापन किस स्तर पर किया गया?क्या बिना दस्तावेजों के सत्यापन के लाइसेंस जारी कर दिया गया? अथवा यह किसी संगठित फर्जीवाड़े, पहचान के दुरुपयोग या गंभीर तकनीकी त्रुटि का परिणाम है? एम.पी. फार्मासिस्ट एसोसिएशन जिलाध्यक्ष मिथुन वप्ता ने ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कर यह सार्वजनिक किया जाए कि संबंधित रजिस्ट्रेशन क्रमांक वर्तमान में किस ड्रग लाइसेंस से लिंक है, वह लाइसेंस किसके नाम पर जारी हुआ तथा उसकी स्वीकृति एवं सत्यापन की प्रक्रिया किन अधिकारियों द्वारा पूरी की गई। एसोसिएशन ने स्पष्ट कहा है कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता, रिकॉर्ड में हेरफेर अथवा फर्जीवाड़ा सामने आता है, तो जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। जिलाध्यक्ष मिथुन वप्ता ने कहा कि ÷यह केवल एक छात्र की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे फार्मेसी समुदाय के विश्वास, पंजीयन व्यवस्था की विश्वसनीयता और विभागीय पारदर्शिता का प्रश्न है। यदि आज इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो भविष्य में हजारों फार्मासिस्टों के अधिकार और करियर भी इसी प्रकार प्रभावित हो सकते हैं। एसोसिएशन ने प्रभावित छात्र को शीघ्र न्याय दिलाने, उसकी समस्या का तत्काल समाधान करने तथा प्रदेशभर में ड्रग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला सचिव दीपक राठौर, जिला उपाध्यक्ष कपिल गौड़ एवं दिलीप प्रजापत भी उपस्थित रहे।

आपदा प्रबंधन की सफलता का आधार जन-सहयोग और बेहतर लोक प्रबंधन : कलेक्टर

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार स्वामी विवेकानंद पी.जी. महाविद्यालय,नीमच में एक दिवसीय भूकंपपूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम का आयोजन जिला स्तर पर किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने कहा कि प्राकृतिक अथवा मानवजनित आपदाएं कभी भी और बिना पूर्व सूचना के आ सकती हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन में पूर्व तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया, प्रभावी समन्वय और जन-सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन में जन-सहयोग और लोक प्रबंधन प्रशासन की प्राथमिकता है।

कलेक्टर श्री चंद्रा ने बताया कि आपदा की स्थिति में आमजन का विश्वास बनाए रखना, घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, घटनास्थल पर एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा जेसीबी, ट्रैक्टर सहित स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का अद्यतन डाटाबेस तैयार रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समय पर संसाधनों की उपलब्धता से राहत एवं बचाव कार्य अधिक प्रभावी ढंग से किए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यशाला में भूकंप प्रबंधन के साथ-साथ औद्योगिक सुरक्षा एवं औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम से संबंधित विषयों पर भी विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। कलेक्टर ने जिले के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों से अपने-अपने उद्योगों की सुरक्षा ऑडिट एवं प्रदूषण नियंत्रण ऑडिट समय पर कराने तथा शासन द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों एवं नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती हेमलता अग्रवाल ने अपने संबोधन में औद्योगिक इकाइयों को प्रशिक्षित सुरक्षा दल गठित करने तथा प्रत्येक उद्योग में प्रभावी आपातकालीन निकासी योजना तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया।इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में संचालित ÷नशे से दूरी है जरूरी 2.0÷ अभियान की जानकारी देते हुए सभी से स्वयं नशे से दूर रहने तथा परिवार और समाज को भी नशामुक्त बनाने के लिए जन-जागरूकता फैलाने की अपील की। अपर कलेक्टर श्री बी.एस. कलेश ने भी आपदा प्रबंधन में विभागीय समन्वय और पूर्व तैयारी के महत्व पर प्रकाश डाला।

रोड किनारे के ढांबों की सघन जांच के निर्देश, कलेक्टर तथा एसपी ने समीक्षा की

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले में सडकों के किनारे विशेष रूप से हाईवे पर मौजूद ढाबों की सघन जांच की जाये। कोई भी गैर कानुनी गतिविधि पाये जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। उक्त जानकारी शुक्रवार को नशा मुक्ति एवं मादक पदार्थ उनमुलन पर आयोजित बैठक में दी गई। कलेक्टर अदिती गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना द्वारा सुशासन भवन सभाकक्ष में नशा मुक्ति एवं पीएम राहत योजना की समीक्षा बैठक में की गई। बैठक में डीएफओ संजय रायखरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बघेल एवं संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि नशा मुक्ति अभियान अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रतियोगिताएं आयोजित करें। ट्रांसपोर्टेशन में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगे हो एवं परिवहन अधिकारी ओचक निरीक्षण करें। पीएम राहत योजना में जितने भी दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति आते हैं उनकी पोर्टल पर एंट्री अनिवार्य करें मोबाइल नंबर भी लिखें। इस दौरान रोड स्पॉट सर्वाधिक दुर्घटना वाले स्थानों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर नशा मुक्ति पर आधारित पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर नशा मुक्ति पर आधारित पोस्टर का विमोचन भी किया गया।

गोरखनाथ आश्रम में खूनी संघर्ष! कब्जे की कोशिश का आरोप, बाबा योगी मौज नाथ गंभीर घायल

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले के जावद नगर स्थित सीएम राइज स्कूल के समीप बने प्राचीन गोरखनाथ आश्रम में शुक्रवार सुबह कब्जे को लेकर विवाद हिंसक हो गया। आश्रम में रह रहे बाबा योगी मौज नाथ (65 वर्ष) के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने आश्रम में घुसकर उन्हें बंधक बनाया और लाठी व लोहे के पाइप से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बाबा को पहले शासकीय अस्पताल जावद पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला चिकित्सालय नीमच रेफर कर दिया गया। उनका उपचार जारी है।

घायल बाबा योगी मौज नाथ ने आरोप लगाया कि मोहन कुमार और गजेंद्र शर्मा गोरखनाथ आश्रम पर कब्जा करना चाहते हैं। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले भी आरोपी कई लोगों के साथ आश्रम पहुंचे थे और वहां बने झोपड़े, कवेलू तथा अन्य सामान में तोड़फोड़ की थी। बाबा के अनुसार, शुक्रवार सुबह दोनों आरोपित करीब 10 से 12 लोगों के साथ दोबारा आश्रम पहुंचे। आरोप है कि सभी ने पहले उन्हें बंधक बनाया और फिर लाठी एवं लोहे के पाइप से हमला कर दिया। इस हमले में उनके हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं।

बाबा योगी मौज नाथ ने बताया कि गोरखनाथ आश्रम वर्ष 1970 से स्थापित है। यहां उनके गुरु निवास करते थे, जिनका वर्ष 1991 में निधन हो गया था। आश्रम परिसर में उनके गुरु सहित तीन संतों की समाधियां हैं, जहां वे वर्षों से नियमित पूजा-अर्चना करते आ रहे हैं। उनका आरोप है कि आश्रम की भूमि पर कुछ लोगों की नजर है और कब्जे की नीयत से लगातार विवाद खड़ा किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

दो दिवसीय कालिदास प्रसंग का आयोजन 21 और 22 जुलाई को होगा, देश के संस्कृत विद्वान शोध पत्रों का वाचन करेंगे

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कालिदास संस्कृत अकादमी एवं म. प्र. संस्कृत परिषद उज्जैन और जिला प्रशासन मंदसौर के संयुक्त तत्वाधान में कालिदास प्रसंग का गौरवपूर्ण आयोजन 21 व 22 जुलाई को श्री कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम महाविद्यालय परिसर में होने जा रहा है।

यह जानकारी देते हुए कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन के निदेशक डॉ गोविंद दत्तात्रेय गन्धै ने बताया कि महाकवि कालिदास द्वारा वर्णित अष्टमूर्ति भगवान श्री पशुपतिनाथ की प्राचीन नगरी दशपुर में विगत एक दशक से अधिक समय से कालिदास प्रसंग का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम के शुभारंभ दिवस 21 जुलाई को प्रातः 8ः30 बजे भगवान श्री पशुपतिनाथजी मंदिर में पूजन एवं कलशार्चन किया जाएगा प्रातः 9ः00 बजे मंगल कलश की शोभायात्रा निकाली जाएगी जो श्री कोल्ड चौराहे से कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम पहुंचेगी और मंगल कलश की स्थापना की जाएगी। आपने बताया कि उद्घाटन विधि प्रातः 10ः30 बजे होगी जिसमें कालिदास को जानो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो विद्यालय स्तर पर आयोजित की गई उसके पुरस्कार वितरण एवं सम्मान का आयोजन होगा। इस सत्र में संस्कृत पालि प्राकृत विभाग महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बडौदा की अध्यक्ष प्रो. श्वेता जेजुरीकर का लोकप्रिय व्याख्यान होगा। मुख्य अतिथि सांसद सुधीर गुप्ता होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर करेंगे। विशेष व विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार, विधायक विपिन जैन, पूर्व विधायक व केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य यशपाल सिंह सिसोदिया नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर, कलेक्टर अदिति गर्ग और प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. ज्योति स्वरूप दुबे सम्मिलित होंगे। उद्घाटन सत्र के पश्चात 21 जुलाई को ही दोपहर 3ः00 बजे से महाकवि कालिदास के साहित्य में नागरिक कर्तव्य लोक जीवन परिवार भाव एवं स्वगौरव विमर्श पर केंद्रित शोध संगोष्ठी के प्रथम सत्र में देशभर से आए संस्कृत के विद्वान अपने शोध पत्रों का वाचन करेंगे। 22 जुलाई को शोध संगोष्ठी का द्वितीय सत्र प्रातः 10ः00 बजे से होगा और उसके पश्चात समापन विधि होगी। कालिदास को जानो प्रतियोगिता महारानी लक्ष्मी बाई स्कूल के प्राचार्य महेश त्रिवेदी संस्कृत व्याख्याता श्रीमती अर्चना दवे के निर्देशन में हुई। कालिदास प्रसंग के इस आयोजन में सहयोग हेतु स्थानीय समिति के सर्वश्री डॉ. घनश्याम बटवाल, ब्रजेश जोशी, नरेन्द्र कुमार त्रिवेदी, गायत्री प्रसाद शर्मा, राव विजय सिंह, बंशीलाल टांक, सत्येंद्र सिंह सोम, जयेश नागर, लोकेश पालीवाल, अनिल संगवानी, महेश त्रिवेदी, संस्कृत व्याख्याता अर्चना दवे, एनसीसी अधिकारी विजयसिंह पुरावत आदि ने नगर के साहित्य एवं संस्कृत प्रेमियों से दो दिवसीय कालिदास प्रसंग के सभी आयोजनों में सम्मिलित होने का अनुरोध किया है।

डेढ़ साल से लंबित एससी-एसटी अत्याचार राहत राशि पर किसान नेता का सरकार पर हमला

मंदसौर में 1.22 करोड़ की राहत राशि अटकी, पीड़ितों को तत्काल भुगतान की मांग

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। किसान नेता श्यामलाल जोकचंद ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पीड़ितों को मिलने वाली राहत राशि के भुगतान में हो रही देरी को लेकर सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि मंदसौर जिले में इस अधिनियम के अंतर्गत 1 करोड़ 22 लाख 25 हजार की राहत राशि पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से लंबित है, जिससे पीड़ित परिवार आर्थिक सहायता के लिए भटकने को मजबूर हैं। जोकचंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर मांग की है कि मंदसौर सहित देशभर में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर पात्र पीड़ितों को तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि संविधान और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम का उद्देश्य पीड़ितों को त्वरित आर्थिक सहायता देकर उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना है, लेकिन भुगतान में हो रही देरी सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत है। उन्होंने कहा कि हत्या, दुष्कर्म, गंभीर मारपीट और अन्य जघन्य अपराधों से प्रभावित दलित एवं आदिवासी परिवार पहले ही गहरे मानसिक और आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में सरकारी सहायता का समय पर नहीं मिलना प्रशासनिक संवेदनहीनता को दर्शाता है।

किसान नेता ने कहा कि यदि अकेले मंदसौर जिले में ही इतनी बड़ी राशि लंबित है, तो प्रदेश और देशभर में लंबित भुगतान की स्थिति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने इसे वंचित और शोषित वर्गों के प्रति सरकार की उदासीनता बताया। इस संबंध में श्यामलाल जोकचंद ने बुधवार को आदिम जाति कल्याण विभाग, मंदसौर पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और लंबित राहत राशि का शीघ्र भुगतान करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो पीड़ित परिवारों के साथ व्यापक जनआंदोलन चलाया जाएगा तथा कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दलित एवं आदिवासी समाज के सम्मान, सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा पीड़ितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा।

सरकार की खामियों को भुगत रहे हैं वृद्ध, विधवा और दिव्यांग, खातों में 4 महीने से नहीं आ रही पेंशन

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। दिव्यांग, वृद्ध, विधवा एवं अनेक प्रकार की पेंशन, जिनका सरकार ने प्रावधान किया है, पिछले 4 महीने से मंदसौर नगर के लगभग 8,000 हितग्राहियों के खाते में नहीं आ रही है। जब ये हितग्राही बैंक में जाते हैं, तो बैंक द्वारा इन्हें नगरपालिका जाने को कह दिया जाता है। लेकिन वहां भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाता है। जबकि लाडली बहना की सभी किश्तें समय पर उन्हें प्राप्त हो रही हैं। समाजसेवी पार्षद सुनील बंसल ने यह मुद्दा उठाते हुए एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि जब हितग्राही नगर पालिका जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि पोर्टल बंद है। तो क्या पिछले 4 महीने से लगातार पोर्टल बंद रह सकता है..? यह भी कहते हैं कि अपडेट होने का काम चल रहा है। हम एक तरफ तो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को पा रहे हैं और गरीब लोगों की पेंशन के पोर्टल को हम 4 महीनों तक अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, यह कहां का न्याय है? श्री बंसल ने कहा कि सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से, जो विभिन्न पेंशन धारकों के खाते में 4 महीने से पेंशन नहीं आई है, अतिशीघ्र उनके खाते में डाले। अनेक लोग ऐसे हैं जो पेंशन के सहारे हैं। यह ?600 जो पेंशन आती है, तो वे उसे ही भगवान समझते हैं। अनेक वृद्ध हमेशा आकर अपना दुखड़ा नगर पालिका के कर्मचारियों के आगे, बैंक कर्मचारियों के आगे और जनप्रतिनिधियों के आगे रो रहे हैं। जिम्मेदार पेंशन शीघ्र प्रारंभ हो, इस बात का प्रयास करें, ताकि जो हितग्राही हैं, उनके जो आंसू सूख चुके हैं, उन्हें भी खुशी का एहसास हो।

चेक बाउंस प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन आज

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 18 जुलाई 2026 को प्रदेशभर में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम (चेक बाउंस) से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय नीमच में आयोजित विशेष लोक अदालत के लिए श्री आलोक कुमार सक्सेना, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अत्याचार निवारण अधिनियम) तथा श्री विशाल खड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की खंडपीठ गठित की गई है। इसी प्रकार जावद तहसील में श्री विनोद कुमार पाटीदार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा श्री अमित नगायच, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की खंडपीठ, जबकि मनासा तहसील में श्री दिनेश कुमार प्रजापति, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा श्री राकेश कुमार मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की खंडपीठ गठित की गई है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,श्रीमती शोभना मीणा ने बताया कि विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस से संबंधित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामे के आधार पर त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण किया जाएगा। उन्होंने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराएं तथा अधिक से अधिक संख्या में राजीनामे के माध्यम से विशेष लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग दें।

कलेक्टर के निर्देश पर चला प्रशासन का बुलडोजर, शासकीय रास्ता कराया अतिक्रमण मुक्त

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जनसमस्या निवारण शिविर में ग्रामीण द्वारा की गई शिकायत पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पालसोड़ा गांव में वर्षों से बाधित शासकीय रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। कार्रवाई के बाद अब ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिलेगी। ग्राम पालसोड़ा निवासी राधाकिशन लखारा ने जनसमस्या निवारण शिविर में शासकीय मार्ग खुलवाने की मांग को लेकर आवेदन दिया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने राजस्व विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश के बाद 16 जुलाई को राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने सीमांकन और पंचनामा की प्रक्रिया पूरी कर सर्वे क्रमांक 2307 तक जाने वाले शासकीय मार्ग से अतिक्रमण हटवाया और रास्ते को दोबारा आमजन के लिए खोल दिया। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा, जिससे पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला स्तरीय मातृ मृत्यु की समीक्षा बैठक संपन्न

प्रथम त्रैमास में गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन एवं गुणवत्तापूर्ण एएनसी सेवाएं सुनिश्चित रें - कलेक्टर

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री हिमांशु चन्द्रा की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला स्तरीय मातृ मृत्यु की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक गर्भवती महिला का गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास में अनिवार्य रूप से पंजीयन कर गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए सभी विभाग समन्वित एवं परिणाममुखी कार्य करें।

कलेक्टर श्री चन्द्रा ने निर्देश दिए कि सभी गर्भवती महिलाओं की समय पर समग्र आईडी बनाकर जानकारी अनमोल पोर्टल पर अद्यतन की जाए, ताकि उन्हें समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उन्होंने गंभीर एवं अति गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की शीघ्र पहचान कर उनके गुणवत्तापूर्ण उपचार एवं प्रबंधन के निर्देश दिए। साथ ही गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप की नियमित जांच सुनिश्चित करने तथा एएनएम द्वारा बीपी उपकरणों का समय-समय पर कैलिब्रेशन कराने को भी कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के चिन्हांकन एवं प्रबंधन की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। शहरी क्षेत्र में कम उपलब्धि पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ संयुक्त सर्वे कर लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने नवजात एवं शिशु मृत्यु के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए एनआईसीयू, एनबीएसयू तथा गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (एचबीएनसी) कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर जोर दिया। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को प्रत्येक नवजात की नियमित गृह आधारित देखभाल तथा उच्च जोखिम वाले बच्चों को तत्काल अस्पताल रेफर करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने तथा जहां एएनएम पदस्थ नहीं हैं, वहां वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से टीकाकरण कराने को कहा।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग को जन्मजात विकृतियों से प्रभावित बच्चों की पहचान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सर्वे कराने तथा सूची स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में क्षय उन्मूलन अभियान, आयुष्मान भारत योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम, गैर संचारी रोग नियंत्रण, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सीएम हेल्पलाइन सहित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई।

बैठक से पूर्व जिला स्तरीय मातृ मृत्यु प्रकरणों की समीक्षा कर सुधारात्मक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद 14 जुलाई से 31 अगस्त तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे की घर-घर जाकर डीएसएस टूल के माध्यम से स्क्रीनिंग की जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अभियान की साप्ताहिक समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमन वैष्णव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश प्रसाद, डब्ल्यूएचओ प्रतिनिधि डॉ. रितेश बजाज, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी सहित स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मप्र विद्युत फेडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अहम बैठक, कर्मचारियों की समस्याओं और आगामी रणनीति पर हुई चर्चा

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। म.प्र. विद्युत फेडरेशन (इंटक) के प्रांतीय पदाधिकारियों ने इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जी संजीवा रेड्डी के साथ बैठक इंटक मुख्यालय नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए ऊर्जा क्षेत्र के संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मी, कंपनी कर्मचारी कि वेतन विसंगतियों को दूर करने,वर्किंग कंडीशन में सुधार करने पर चर्चा करते हुए आगामी रणनीति पर सार्थक चर्चा हुई। बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष श्री बी डी गौतम भोपाल, प्रांतीय महामंत्री डीएस चंद्रावत मंदसौर, प्रांतीय उपाध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव झाबुआ, प्रांतीय संगठन सचिव केके पुरोहित महेश्वर, योगेश डोंगरे खंडवा, आर आर पाराशर सागर, अतिन्द्र मोहन वर्मा खरगोन, राजेंद्र सिंह चौहान धार, प्रेम रावल धार, संजय वोहरा रतलाम, जी के वार्ष्णेय मुरैना, लोकेश पचौरी ग्वालियर, शंकर सिंह तिवारी सतना, आर पी सिंह बैतूल, संजय सोनी भोपाल, पवनीश चोपड़ा भोपाल, अकबर खान भोपाल, अभय श्रीवास्तव भोपाल, दशरथ सिंह मंडलोई, दीपक पांचाल झाबुआ उपस्थित थे।

जिला पुरातत्व,पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक 23 जुलाई को

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पर्यटन संभावनाओं का पूर्ण दोहन करने हेतु विभिन्न शासकीय विभाग/स्वयंसेवी संगठनों तथा पर्यटन से संबंधित हितग्राहियों आदि के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये जिला स्तरीय पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। कार्यकारिणी समिति की बैठक कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में 23 जुलाई 2026 को दोपहर 02ः30 बजे,कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जाएगी।सर्व संबंधितों से बैठक में उपस्थिति की अपेक्षा की गई है।

सम्पादकीय

भारत के लिए अमेरिका सदैव ट्रबलसम फ्रेंड् (दुखदाई मित्र)

भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका तथा रूस से अपने संबंध विस्तारित करने का प्रयास किया पर रूस ने सदैव एक सच्चे मित्र की भूमिका निभाई पर कई सोपनो में अमेरिका केवल अपनी आर्थिक नीतियों को मजबूत करने के लिए भारत से संबंध बनाते रहा है एवं भारत से ज्यादा पड़ोसी पाकिस्तान देश को वरीयता प्रदान करता रहा है एवं उसे आर्थिक तथा सामरिक मदद भी करता रहा। अमेरिका का सदैव यह प्रयास रहा कि भारत में अंदरूनी तथा बाहरी अस्थिरता बनी रहे और यही कारण है कि वह पाकिस्तान को सदैव भारत के खिलाफ भड़काता उकसाता रहा है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक मित्रता में अमेरिका का आर्थिक पढ़ला हमेशा भारी रहा है यह अलग बात है कि भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और अपनी स्वायत्त छवि को विदेशों में कायम रखा और एक स्वतंत्र गुटनिरपेक्ष नीति पर आगे चला रहा। विश्व राजनीति में अमेरिका एक ऐसी महाशक्ति के रूप में स्थापित रहा है जिसकी विदेश नीति का मूल आधार आदर्शवाद से अधिक राष्ट्रीय हित और आर्थिक लाभ रहा है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों का मानना है कि कोई भी राष्ट्र स्थायी मित्र या शत्रु नहीं रखता, बल्कि उसके स्थायी हित होते हैं। अमेरिका ने भी अपने राष्ट्रीय हितों, आर्थिक प्रभुत्व और सामरिक वर्चस्व को सर्वोपरि रखते हुए विश्व के देशों के साथ संबंध स्थापित किए हैं। यही कारण है कि अनेक बार वह मित्र दिखाई देता है, तो कई बार उसके निर्णय मित्र देशों के लिए भी असहज और चिंताजनक साबित होते हैं।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका ने स्वयं को वैश्विक आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया। उसने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, व्यापारिक समझौतों और सुरक्षा गठबंधनों के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार किया। अमेरिका की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विश्व बाजारों तक पहुंच बनाए रखना, ऊर्जा संसाधनों की सुरक्षा करना और अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना रहा है।

इराक, अफगानिस्तान, लैटिन अमेरिका, पश्चिम एशिया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी हस्तक्षेपों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र, मानवाधिकार और सुरक्षा जैसे मुद्दों के साथ-साथ आर्थिक और सामरिक हित भी उसकी नीतियों के केंद्र में रहे हैं। इसलिए आलोचक अमेरिका को हित-आधारित मित्र या ट्रबलसम फ्रेंड की संज्ञा देते हैं।

भारत के संदर्भ में अमेरिकी दृष्टिकोण- भारत की स्वतंत्रता के बाद अमेरिका और भारत के संबंध सदैव सरल नहीं रहे। शीतयुद्ध काल में भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई, जबकि अमेरिका पाकिस्तान को अपने सामरिक सहयोगी के रूप में देखता था। पाकिस्तान को सैन्य सहायता, आधुनिक हथियारों और आर्थिक सहयोग ने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित किया।

1965 और 1971 के युद्धों के दौरान भी अमेरिकी नीतियों को लेकर भारत में अनेक प्रश्न उठे। विशेष रूप से 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय अमेरिकी प्रशासन का झुकाव पाकिस्तान की ओर दिखाई दिया। इससे भारतीय जनमानस में यह धारणा मजबूत हुई कि अमेरिका दक्षिण एशिया में भारत की अपेक्षा पाकिस्तान को सामरिक दृष्टि से अधिक महत्व देता है।

हालांकि यह भी सत्य है कि समय के साथ परिस्थितियां बदलीं। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत-अमेरिका संबंधों में नई निकटता आई। सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और परमाणु सहयोग जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों ने उल्लेखनीय साझेदारी विकसित की। 2008 का असैनिक परमाणु समझौता इस संबंध का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है।

विश्वास और सावधानी के बीच भारत- भारत और अमेरिका आज रणनीतिक साझेदार हैं, किंतु यह साझेदारी पूर्ण विश्वास पर नहीं बल्कि पारस्परिक हितों पर आधारित है। अमेरिका जहां चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत को महत्वपूर्ण साझेदार मानता है, वहीं भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है। रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान के प्रश्न और वैश्विक व्यापारिक नीतियों पर कई बार दोनों देशों के दृष्टिकोण अलग दिखाई देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारत को अमेरिका के साथ सहयोग तो बढ़ाना चाहिए, लेकिन अपनी विदेश नीति का निर्धारण राष्ट्रीय हितों और आत्मनिर्भर सामरिक क्षमता के आधार पर करना चाहिए। वैसे भी विदेश नीति परिपेक्ष में किसी भी देश के साथ अमेरिका अमेरिका को भी केवल मित्र या शत्रु की संकीर्ण परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। वह एक ऐसी महाशक्ति है जो अपने राष्ट्रीय, आर्थिक और सामरिक हितों के अनुसार निर्णय लेती है। भारत के लिए भी आवश्यक है कि वह भावनाओं के बजाय यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विश्वास से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित और सामरिक संतुलन होते हैं। भारत को अमेरिका सहित सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संतुलित संबंध रखते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामरिक शक्ति को सुदृढ़ करना होगा।

मानव का सूक्ष्म तंत्र और सहजयोग

हम क्या हैं? हमारे भीतर परमात्मा ने कौन-कौन सी सूक्ष्म व्यवस्थाएँ स्थापित की हैं, और किस तंत्र के माध्यम से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं–इसी का ज्ञान सहजयोग प्रदान करता है। परमात्मा ने मनुष्य के भीतर पूर्ण तैयारी पहले से ही कर रखी है; आवश्यकता केवल उस दिव्य शक्ति को जागृत करने की है। जब मनुष्य आत्मसाक्षात्कार (आलोकित अवस्था) प्राप्त कर लेता है, तब यह समस्त ज्ञान सहज रूप से अनुभव में आने लगता है।

हमारे शरीर में स्वचालित नाड़ीतंत्र कार्य करता है, जिसके तीन प्रमुख सूक्ष्म मार्ग हैं–ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी (बायाँ मार्ग) बाएँ अनुकम्पी नाड़ीतंत्र का पोषण करती है। इसे चन्द्र नाड़ी भी कहा जाता है और यह हमारे भावनात्मक पक्ष, भूतकाल तथा अवचेतन मन से संबंधित है। पिंगला नाड़ी (दायाँ मार्ग) दाएँ अनुकम्पी नाड़ीतंत्र के लिए कार्य करती है। इसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है तथा यह हमारी बुद्धि, कर्मशीलता, भविष्य और अतिचेतन मन का संचालन करती है। इन दोनों के मध्य स्थित सुषुम्ना नाड़ी वह दिव्य मार्ग है जिससे होकर कुण्डलिनी ऊपर उठती है, ब्रह्मरन्ध्र का भेदन करती है और साधक का सर्वव्यापक परमचैतन्य से योग स्थापित होता है। बायाँ और दायाँ अनुकम्पी नाड़ीतंत्र परस्पर पूरक होते हुए भी विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं।

सुषुम्ना मार्ग पर सात प्रमुख सूक्ष्म ऊर्जा चक्र स्थित हैं, जिनका निर्माण मानव की आध्यात्मिक उत्क्रान्ति के साथ हुआ है। ये हैं–मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र , अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र तथा सहस्त्रार चक्र। इन चक्रों के अतिरिक्त कुछ सहायक चक्र भी होते हैं, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कुण्डलिनी मनुष्य के भीतर स्थित शुद्ध इच्छा-शक्ति है, जिसका उद्देश्य हमें सर्वव्यापक परमचैतन्य से जोड़ना है। यह शक्ति पवित्र त्रिकोणाकार अस्थि सेक्रम बोन में साढ़े तीन कुण्डलों के रूप में विराजमान रहती है। "Sacrum" शब्द का अर्थ ही पवित्र अस्थि है, जो इस शक्ति की दिव्यता को दर्शाता है। सहजयोग में आत्मसाक्षात्कार के समय यही कुण्डलिनी जागृत होकर सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठती है और सहस्त्रार चक्र का भेदन कर साधक को परमात्मा के सर्वव्यापक प्रेम एवं चैतन्य से जोड़ देती है।

सहजयोग के अनुसार हमारे हृदय में आत्मा का निवास है, जो स्वचालित नाड़ीतंत्र का संचालन करती है। यह आत्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा का प्रतिबिम्ब है, जबकि कुण्डलिनी परमात्मा की आदिशक्ति का प्रतिबिम्ब है। जब आत्मा का प्रकाश और कुण्डलिनी की जागृति एक साथ अनुभव में आती है, तभी मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाता है और आध्यात्मिक उत्क्रान्ति का अंतिम चरण पूर्ण होता है।

आज का मॉनसून, कल का इतिहास नहीं – भविष्य का फैसला है

प्रकृति चेतावनी देने के लिए शब्दों का सहारा नहीं लेती; वह अपने संकेत छोड़ती है–कभी प्यास से फटी धरती पर, कभी पहाड़ों से टूटते मलबे में, तो कभी एक रात की बारिश में ढह गए घरों की खामोशी में। 2026 का मॉनसून भी ऐसा ही एक मौन संदेश था, जिसे अनसुना करना आने वाले कल से आंखें मूंदना होगा। जून में सामान्य से लगभग 40 प्रतिशत से अधिक वर्षा की कमी ने खेतों की उम्मीदें सुखा दीं। एल नीनो के प्रभाव में किसान आसमान निहारते रहे, लेकिन बादल बेरुख़ रहे। फिर जुलाई ने अचानक करवट बदली। मुंबई, वायनाड, रत्नागिरी सहित कई क्षेत्रों में कुछ दिनों की मूसलाधार बारिश ने साबित कर दिया कि अब खतरा बारिश के कम या अधिक होने में नहीं, बल्कि उसके बेकाबू और असंतुलित स्वरूप में है। 2026 का मॉनसून इस सच्चाई की गवाही बन गया कि जलवायु परिवर्तन ने मौसम का मिज़ाज बदल दिया है।

यह बदलाव आकस्मिक नहीं, बल्कि विज्ञान की वर्षों पुरानी चेतावनी का साकार रूप है। वैज्ञानिकों के अनुसार, गर्म होती पृथ्वी का वातावरण पहले से अधिक नमी समेट रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का बढ़ता तापमान इसे ऊर्जा दे रहा है। नतीजा यह है कि बादल अब ठहरकर नहीं, टूटकर बरसते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, जुलाई के शुरुआती दिनों में मुंबई (सांताक्रुज स्टेशन) में 600ङ्क900 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई, जो जुलाई के पूरे महीने के औसत का बड़ा हिस्सा थी। दूसरी ओर, वायनाड में मौसमी वर्षा सामान्य से कम रही, लेकिन दो दिनों की मूसलाधार बारिश ने टनल निर्माण स्थल पर मिट्टी का पहाड़ ढहा दिया। इस हादसे में कई मजदूरों की जान गई, कुछ लापता रहे। यह महज़ हादसा नहीं, बल्कि बदलते जलवायु दौर की भयावह तस्वीर है, जहाँ कम वर्षा वाला मौसम भी विनाश की इबारत लिख सकता है।

2026 के मॉनसून ने केवल शहरों को नहीं, हमारी विकास-दृष्टि को भी कठघरे में खड़ा कर दिया। कंक्रीट के फैलते जंगलों ने पानी के प्राकृतिक रास्ते निगल लिए। नतीजा था–मुंबई के मानखुर्द में चॉल ढह गई, पालघर में बाढ़ दस से अधिक जिंदगियां बहा ले गई, पेड़ उखड़े, दीवारें गिरीं और शहर दिनों तक थम गए। यह तबाही सिर्फ आसमान से बरसे पानी की नहीं थी; जर्जर ड्रेनेज व्यवस्था, रिक्लेम्ड भूमि पर अनियोजित निर्माण और प्रकृति की कीमत पर खड़ा विकास भी इसके भागीदार थे। जलवायु विशेषज्ञ वर्षों से चेताते रहे हैं कि मध्य भारत में 1950 के बाद अत्यधिक वर्षा की घटनाएं लगभग तीन गुना बढ़ चुकी हैं। 2026 ने उस चेतावनी को आंकड़ों से उठाकर सड़कों, बस्तियों और ज़िंदगियों पर लिख दिया। अब बारिश मौसम नहीं, कुछ घंटों में पूरे महीने का संतुलन और शहरों की व्यवस्था बहा ले जाती है। 2026 के मॉनसून ने एक भ्रम तोड़ दिया–सूखा और बाढ़ अब विरोधी नहीं, बल्कि एक ही जलवायु संकट के दो रूप हैं। एल नीनो ने पहले बारिश रोकी, फिर गर्म वातावरण ने संचित नमी उलीच दी। सूखी धरती पानी सोख न सकी; वही जल मैदानों में बाढ़ और पहाड़ों में भूस्खलन बन गया। बदलता मौसम चेतावनी है कि अब खतरा वर्षा की मात्रा से अधिक उसकी तीव्रता और असंतुलन में है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, वैश्विक तापमान 1.5-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर कई क्षेत्रों में आर्द्र गर्मी गंभीर संकट बन सकती है। यानी आने वाले समय में चुनौती केवल सूखे और बाढ़ की नहीं; बारिश के बाद की दमघोंटू उमस जनस्वास्थ्य, श्रम क्षमता और अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगी।

2026 के मॉनसून ने एक नया शब्द सिखाया है–वैरिएबिलिटी। अब बारिश का आकलन उसकी कुल मात्रा से नहीं, बल्कि उसके समय, अवधि और तीव्रता से होगा। कई दिनों का सूखा और फिर एक-दो दिनों में पूरे महीने जितनी वर्षा–यही नया पैटर्न खेती, पर्यावरण और शहरों की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। किसानों को कम अवधि वाली फसलें, जलवायु-अनुकूल बीज और सटीक मौसम पूर्वानुमान अपनाने होंगे। शहरों को स्पॉन्ज सिटी मॉडल विकसित करना होगा, ताकि वर्षा जल सड़कों पर बहने के बजाय जमीन में समा सके। वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां वैज्ञानिक आकलन और कठोर मानकों से संचालित हों; क्योंकि बदलते मौसम में यही विकास की सबसे विश्वसनीय बुनियाद है।

सबसे बड़ी भूल यह होगी कि जलवायु संकट का समाधान केवल राष्ट्रीय योजनाओं में खोजा जाए। 2026 का मॉनसून बताता है कि पिछले दो वर्षों की अच्छी वर्षा से अधिकांश जलाशय भरे होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर भारी तबाही हुई। साफ है, बड़े बांध, घोषणाएं और राहत पैकेज तब तक पर्याप्त नहीं होंगे, जब तक हर शहर, गांव और पहाड़ी क्षेत्र अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप तैयार न हो। वेटलैंड्स का संरक्षण, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक, नदियों और प्राकृतिक जलमार्गों का पुनर्जीवन तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को विकास की आधारशिला बनाना अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन भविष्य की आशंका नहीं, वर्तमान का यथार्थ है–और इसकी सबसे बड़ी कीमत आने वाली पीढ़ियां नहीं, आज का समाज चुका रहा है।

हर आपदा केवल नुकसान नहीं छोड़ती, वह हमारी प्राथमिकताओं का भी परीक्षण करती है। 2026 का मॉनसून इसी कसौटी पर हमें परख गया। उसने स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति की सीमाओं की अनदेखी कर किया गया विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। अब समय राहत और मुआवजे की घोषणाओं से आगे बढ़कर विकास की दिशा बदलने का है। इंफ्रास्ट्रक्चर को जलवायु-अनुकूल, नीतियों को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप और विकास को पर्यावरण का प्रतिद्वंद्वी नहीं, उसका सहभागी बनाना होगा। चेतावनी स्पष्ट है, निर्णय हमारे हाथ में है। यदि इस संकेत को भी अनसुना किया गया, तो आने वाले मॉनसून केवल नई आपदाएं नहीं लाएंगे, बल्कि हमारी विकास-यात्रा की नींव को भी कठघरे में खड़ा कर देंगे। यही 2026 के मॉनसून की सबसे बड़ी सीख है और यही हमारे समय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

-प्रो. आरके जैन

नई यूरिया नीति ही काफी नहीं, सब्सिडी सुधार अब भी जरूरी

नई राष्ट्रीय यूरिया नीति कृषि क्षेत्र से जुड़े इस महत्त्वपूर्ण कच्चे माल से जुड़ी समस्या का आंशिक समाधान प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है ताकि इसे वैश्विक आपूर्ति झटकों से बचाया जा सके। भारत अपनी वार्षिक 4 करोड़ टन यूरिया मांग का 25 फीसदी आयात करता है। पश्चिम एशिया युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के बाद जब तक चीन ने अपना अस्थायी निर्यात प्रतिबंध नहीं हटाया तब तक कीमतें 40 से 50 फीसदी तक बढ़ गईं। नीति का लक्ष्य 8 या 9 यूरिया संयंत्र स्थापित करना है जिनकी उत्पादन क्षमता 1 करोड़ टन होगी। यानी वर्तमान में आयात की जाने वाली मात्रा के समतुल्य।

इसके लिए प्रोत्साहन संरचना में बदलाव किए गए हैं। इनमें स्थिर और परिवर्तनीय लागतों को अलग करना, इक्विटी पर रिटर्न की गणना के लिए 12-16 फीसदी का बैंड लागू करना और विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए मौजूदा विनिमय दर के आधार? पर स्थिर लागतों को चार साल बाद रुपये में बदलना शामिल है। आत्मनिर्भरता का उद्देश्य निस्संदेह एक तात्कालिक समस्या का समाधान करता है क्योंकि निकट भविष्य में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की अनिश्चितताएं बनी रहेंगी। लेकिन जब भारत की उर्वरक नीति की गहरी संरचनात्मक समस्याओं के संदर्भ में देखा जाए तो यह अपर्याप्त प्रतीत होता है।

मूल समस्या भारत की उर्वरक सब्सिडी संरचना में है जो अमोनिया-आधारित यूरिया (एन) को फॉस्फेट आधारित (पी) और पोटैशियम आधारित (के) पोषक तत्वों पर प्राथमिकता देती है। जहां बाद के दोनों पोषक तत्वों पर सब्सिडी पोषक तत्व सामग्री के आधार पर दी जाती है वहीं यूरिया पर सपाट दर से सब्सिडी दी जाती है। वर्तमान में किसान 45 किलो का यूरिया बैग 242 रुपये में खरीदता है जबकि सरकार को इसकी लागत 2,200 रुपये से 4,000 रुपये तक आती है।

यह इस पर निर्भर करता है कि यूरिया घरेलू रूप से निर्मित है या आयातित। आश्चर्य नहीं कि वर्षों में यूरिया सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उर्वरक बन गया है जिससे वार्षिक सब्सिडी अस्थिर स्तर तक पहुंच गई है। आमतौर पर यूरिया ही उर्वरक सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जिसके लिए चालू वित्त वर्ष में 1.71 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। पश्चिम एशिया में संघर्ष के बाद वैश्विक कीमतों में तेजी से वृद्धि होने के कारण यह आंकड़ा काफी अधिक होने की संभावना है। अधिक घरेलू संयंत्र स्थापित करना आयात पर निर्भरता को कुछ हद तक कम कर सकता है, लेकिन अन्य समस्याओं पर भी विचार करना आवश्यक है। पहला, सरकार का अनुमान है कि यूरिया की मांग हर साल 5 फीसदी बढ़ रही है। एक यूरिया संयंत्र बनाने में लगभग दो साल लगते हैं। मान लें कि सभी नए संयंत्र समय पर बनकर 1 करोड़ टन उत्पादन शुरू कर दें यानी वर्तमान घरेलू कमी के बराबर, तब भी भारत मांग के ग्राफ से पीछे ही रहेगा।

-सुनील कुमार महला

बैंकों में उच्च पदों के लिए लोगों की उपलब्धता सीमित क्यों?

मुंबई की मॉनसूनी बारिश ने मुझे दो बैंकर मित्रों के साथ कॉफी पर एक शाम बिताने पर विचार के लिए 'हां' कहने को प्रेरित किया, जो एचडीएफसी बैंक के अगले अंशकालिक चेयरमैन के बारे में अटकलबाजी का आनंद ले रहे थे ।

1985 बैच के आईएएस अधिकारी और आर्थिक मामलों तथा निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के पूर्व सचिव अतनु चक्रवर्ती के मार्च में अंशकालिक चेयरमैन पद से इस्तीफा देने के बाद से ही अटकलों का दौर चलता रहा। चक्रवर्ती ने कहा कि पिछले दो वर्षों में उन्होंने बैंक के भीतर कुछ ऐसी घटनाओं और तौर-तरीकों को देखा है जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं थे।

दोनों मित्र बैंकरों में से एक को पूरा यकीन था कि एचडीएफसी बैंक किसी अन्य आईएएस अधिकारी को नियुक्त नहीं करेगा, जबकि दूसरे को लगता था कि कोई अन्य आईएएस अधिकारी ही आकर पदभार संभालेगा।

संयोगवश, चक्रवर्ती और इस बैंक के पहले अफसरशाह-चेयरमैन (2010-15) सीएम वासुदेव के बाद राजीव कुमार इस पद को संभालने वाले तीसरे आईएएस अधिकारी होंगे।

वैसे तो किसी आईएएस अधिकारी का बैंक के अंशकालिक चेयरमैन का पद संभालना कोई असामान्य बात नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक में लगातार दो बार ऐसा हुआ है- गिरीश चंद्र चतुर्वेदी (जुलाई 2018-जून 2024) जो पेट्रोलियम सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और उनके ठीक बाद भारत के 31वें कैबिनेट सचिव पी.के. सिन्हा। दोनों ही 1977 बैच के आईएएस अधिकारी थे।

1978 बैच के आईएएस अधिकारी सीएस राजन, जो 2016 में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, जनवरी 2024 से कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालिक चेयरमैन हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के पूर्व चेयरमैन देवा?शिष पांडा ने पिछले सप्ताह बंधन बैंक के अंशकालिक चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला।

सार्वजनिक क्षेत्र में, बैंक ऑफ बड़ौदा में इसी पद पर गुजरात कैडर के 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हसमुख अधिया थे, जिन्होंने वित्त सचिव और राजस्व सचिव के रूप में कार्य किया था। गुजरात कैडर के ही 1982 बैच के आईएएस अधिकारी तपन राय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में थे।

आईएएस अधिकारी न मिलने पर, बैंक आमतौर पर इस पद के लिए पूर्व केंद्रीय बैंक अधिकारी या किसी प्रतिष्ठित वाणिज्यिक बैंकर को चुनते हैं। तीसरा विकल्प अर्थशास्त्री या शिक्षाविद् होते हैं। कुछ उदाहरणों के तौर पर, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन ऐक्सिस बैंक के अंशकालिक चेयरमैन हैं। उनके सहयोगी आरएस गांधी येस बैंक में इसी पद पर हैं और एक अन्य डिप्टी गवर्नर, एचआर खान, एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक से जुड़े हैं।

प्रख्यात अर्थशास्त्री और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार शंकर आचार्य कोटक महिंद्रा बैंक में गैर-कार्यकारी चेयरमैन (2006-18) थे। भारत सरकार के 12वें मुख्य आर्थिक सलाहकार और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी बंधन बैंक के पहले अंशकालिक चेयरमैन थे।

बेशक, राकेश मखीजा जैसे अपवाद भी हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से इंजीनियर, एसकेएफ समूह में औद्योगिक बाजार प्रभाग (रणनीतिक उद्योग) के पूर्व अध्यक्ष और समूह कार्यकारी समिति के सदस्य रहे मखीजा जुलाई 2019 से अक्टूबर 2023 के बीच ऐक्सिस बैंक के अंशकालिक चेयरमैन भी रहे।

कॉफी पीते हुए इस बात पर गरमागरम बहस हुई कि आईएएस अधिकारी और पूर्व केंद्रीय बैंक अधिकारी किसी बैंक के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। एक ने केंद्रीय बैंक और सरकार के साथ 'तालमेल बिठाने' का संकेत दिया, लेकिन अंत में हम तीनों इस बात पर सहमत हुए कि उनमें से अधिकांश के पास एक विशेष कौशल होता है जो किसी बैंक को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक है।

एक आईएएस अधिकारी, जो जिला कलेक्टर से वित्त सचिव जैसे पद तक पहुंचा हो, उसके पास जबरदस्त प्रशासनिक कौशल होता है। हो सकता है कि उनमें वित्तीय ज्ञान की कमी हो, लेकिन वे आम तौर पर दूसरों की तुलना में चीजों को जल्दी समझते हैं और एक व्यापक दृष्टिकोण लाते हैं जो बैंक चलाने में सहायक होता है। इसी प्रकार, एक केंद्रीय बैंकर, उद्योग के गहन ज्ञान के अलावा, नियामकीय कठोरता, अनुपालन और प्रशासन लाता है, जो सार्वजनिक विश्वास पर आधारित संस्था की आधारशिला है।

शाम की चर्चा में बैंकिंग क्षेत्र में दो महत्त्वपूर्ण कार्यकारी नियुक्तियों पर भी विचार-विमर्श हुआ। क्या शशि जगदीशन को एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में एक और कार्यकाल मिलेगा? और जनवरी 2027 में कोटक बैंक के प्रमुख अशोक वासवानी की कुर्सी कौन संभालेगा?

मुख्य ध्यान निदेशक मंडल और सीईओ के साथ-साथ अंशकालिक चेयरमैन पदों के लिए प्रतिभाओं की घटती संख्या पर था। वास्तव में, प्रतिभाओं की कमी है, लेकिन चुनौती चुनौती ऐसी नहीं है जिसे पार न किया जा सके। इस घटना के पीछे दो प्रमुख मुद्दे हैं।

पहली बात तो यह है कि बैंक सीईओ के वेतन पैकेज को मंजूरी देने में आरबीआई ज्यादा उदार नहीं है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के मामले में ऐसा नहीं है। कुछ एनबीएफसी प्रमुखों को बड़े बैंकों के अधिकारियों की तुलना में कहीं अधिक वेतन पैकेज मिलता है। कई बैंकर बैंकिंग छोड़कर एनबीएफसी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो रहा है।

क्या स्वतंत्र निदेशकों को इससे छूट नहीं मिलनी चाहिए? सरकार अधिसूचना जारी करके स्वतंत्र निदेशकों के लिए अपवाद बना सकती है। यदि ऐसा किया जाता है, तो कई और सक्षम पेशेवर इस पद के लिए आगे आएंगे।

अफसरशाहों और केंद्रीय बैंक अधिकारियों पर अत्यधिक निर्भरता इस असहज वास्तविकता को दर्शाती है कि बैंकिंग प्रणाली अपने बोर्डरूम के लिए पर्याप्त संख्या में कुशल नेतृत्वकर्ताओं की आपूर्ति करने में संघर्ष कर रही है। न केवल सीईओ और पूर्णकालिक निदेशकों के लिए, बल्कि स्वतंत्र निदेशकों के वेतनमान पर भी आरबीआई द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

अंततः, आईएएस अधिकारी नियामक क्षेत्र में भी अपना दबदबा बनाए हुए हैं। पांच साल के अंतराल के बाद (जब रघुराम राजन और ऊर्जित पटेल केंद्रीय बैंक के प्रमुख थे) आईएएस अधिकारी रिजर्व बैंक के मुख्यालय लौट आए हैं।

स्थापना के बाद से, एक अपवाद को छोड़कर (भारतीय जीवन बीमा निगम के पूर्व प्रमुख टीएस विजयन), आईआरडीएआई का नेतृत्व अफसरशाहों द्वारा ही किया जाता रहा है। बाजार नियामक के मामले में भी यही स्थिति है। आईएएस अधिकारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के प्रमुख लगभग निरंतर रूप से रहे हैं, एक अपवाद माधवी पुरी बुच (2022-25) को छोड़कर । उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद, तुहिन कांत पांडेय (ओडिशा कैडर के 1987 बैच के अधिकारी) ने यहां आईएएस अधिकारियों की वापसी की घोषणा की।

हमारी चर्चा का अंतिम भाग सबसे रोचक था। वर्तमान में, तीनों प्रमुख वित्तीय नियामक निकाय ङ्क आरबीआई, सेबी और आईआरडीएआई- आईएएस अधिकारियों के नेतृत्व में हैं। अजय सेठ वर्तमान पदभार संभालने से पहले वित्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि 1990 बैच के आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा ने राजस्व सचिव रहते हुए आरबीआई गवर्नर का पदभार संभाला था और पांडेय वित्त तथा राजस्व सचिव के रूप में सेवारत रहते हुए सेबी में शामिल हुए थे।

ये तीनों वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) के सदस्य हैं। वित्त मंत्री इस सर्वोच्च स्तर के, गैर-वैधानिक निकाय के प्रमुख होते हैं, जिसकी स्थापना दिसंबर 2010 में व्यापक आर्थिक पर्यवेक्षण को मजबूत करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और विभिन्न वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए की गई थी।

-डॉ. सुधाकर आशावादी

मानव पूंजी की खाई पाटे बिना अधूरा रहेगा भारत का विकास

आम तौर पर यह माना जाता है कि आगामी कुछ दशकों तक भारत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सालाना 7-8 फीसदी की वृद्धि दर कायम रखेगा और जल्दी ही उच्च-मध्य आय वर्ग वाले देशों की श्रेणी में और यहां तक कि उच्च आय वाले देशों की श्रेणी में पहुंच जाएगा (विकसित भारत का सपना)। ऊपर से देखने पर तो यह रफ्तार प्रभावशाली लगती है। नए एक्सप्रेसवे ग्रामीण इलाकों को चीरते हुए निकल रहे हैं, छोटे शहरों में चमचमाते हवाई अड्डे खुल रहे हैं और विश्वस्तरीय डिजिटल ढांचा अरबों के लेनदेन को रियल टाइम या तात्कालिक समय में संभाल रहा है।

लेकिन भारत ऊपरी-मध्य-आय वाले देशों की श्रेणी में प्रवेश करने से पहले ही एक तरह की बाधा का जोखिम उठा रहा है। इसकी वजह एकदम साधारण, स्पष्ट और कम संबोधित है। वह वजह है मानव पूंजी के विकास में गहरी और प्रणालीगत विफलता जिसे अब किसी देश की समृद्धि का सबसे महत्त्वपूर्ण कारक माना जा रहा है।

परंपरागत रूप से शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वृद्धि को अधिक श्रमिकों, अधिक भूमि और अधिक मशीनों को जोड़ने की यांत्रिक प्रक्रिया के रूप में देखा। लेकिन जब इसे आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर लागू किया जाता है तो यह काम नहीं करता है। भौतिक निवेश जैसे कोई कारखाना, कठोर घटते रिटर्न के नियम के अधीन होता है। कोई देश अपने ट्रैक्टरों या कंप्यूटरों का भंडार दोगुना कर सकता है लेकिन उसे तकनीकी रूप से सक्षम कामगारों की संख्या भी दोगुनी करनी होगी ताकि वे उन्हें चला सकें। वर्ष 1992 में अर्थशास्त्री ग्रेगरी मैनकिव, डेविड रोमर और डेविड वील ने मानव पूंजी यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और विशिष्ट कौशल के सामूहिक मिश्रण को उत्पादन के स्वतंत्र कारक के रूप में अलग किया।

अब भूगोल, संस्कृति या प्राकृतिक संसाधन नहीं ब?ल्कि मानव पूंजी यह तय करती है कि आखिर क्यों कुछ देश अमीर बन जाते हैं जबकि अन्य ठहरे रहते हैं। पुराने मॉडलों में कोई देश यदि भौतिक मशीनरी में किसी अन्य की तुलना में चार गुना अधिक निवेश करता था तो वह अंततः केवल दोगुना ही समृद्ध होता था। लेकिन मैनकिव-रोमर-वेल मॉडल यह साबित करता है कि जब उच्च भौतिक पूंजी निवेश को उच्च मानव पूंजी निवेश से गुणा किया जाता है तो यह एक चक्रवृद्धि प्रभाव पैदा करता है। यानी प्रति श्रमिक संपदा में 16 गुना उछाल।

इसके अलावा विकास सिद्धांतकार रॉबर्ट लुकास और पॉल रोमर ने दिखाया कि मानव पूंजी के पास एक अनूठा आर्थिक लाभ है। यह घटते रिटर्न के नियम से प्रभावित नहीं होती।

केवल एक शैक्षणिक अवधारणा नहीं है। यह 20वीं सदी के सबसे बड़े आर्थिक चमत्कारों के पीछे की सच्चाई है। 1953 में दक्षिण कोरिया एक युद्धग्रस्त राष्ट्र था, जहां वयस्क साक्षरता दर केवल 20 फीसदी थी। उसके पास न तेल था, न खनिज, और न ही कोई उल्लेखनीय भौतिक संपत्ति। राज्य ने शिक्षा नीति को अपनी मुख्य औद्योगिक नीति माना। उसने 1960 के दशक में हल्के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निरक्षरता समाप्त की, 1970 के दशक में भारी उद्योगों को आपूर्ति देने के लिए व्यावसायिक तकनीकी स्कूलों का विस्तार किया और 1980 के दशक में विश्वविद्यालयों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी संसाधनों से भर दिया। आज यह एक वैश्विक नवाचार महाशक्ति के रूप में खड़ा है।

अचानक 1965 में आज़ादी मिलने पर सिंगापुर को भी वैसी ही मुश्किल शुरुआत का सामना करना पड़ा। घरेलू जल आपूर्ति तक न होने के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने कहा कि द्वीप की एकमात्र संपत्ति उसके लोग हैं। इस नगर-राज्य ने अपने शिक्षा तंत्र को विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सटीक तकनीकी आवश्यकताओं के साथ तालमेल वाला बनाया। बाद में, कौशल को अप्रचलित होने देने के बजाय इसने सतत राज्य-वित्त पोषित वयस्क पुनः प्रशिक्षण की पहल की।

चीन ने भी मानव पूंजी को ही अपनाया। 1978 में तंग श्याओफिंग द्वारा अर्थव्यवस्था खोले जाने से पहले दशकों के सार्वजनिक निवेश ने पहले ही व्यापक बुनियादी साक्षरता और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित कर दी थी। जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं पहुंचीं तो उन्हें केवल सस्ता श्रम ही नहीं मिला बल्कि एक अत्यधिक अनुशासित, साक्षर कार्यबल भी मिला जो खाकों को पढ़ने और जटिल असेंबली को निष्पादित करने में सक्षम था। इसके बाद चीन ने मानव इतिहास में सबसे बड़ा उच्च शिक्षा विस्तार किया। आज वह हर साल 1 करोड़ से अधिक छात्रों को स्नातक कर रहा है, जिनमें भारी संख्या इंजीनियरिंग की होती है,ताकि बिजली से चलने वाले वाहनों और हरित प्रौद्योगिकी में विश्व का नेतृत्व कर सके।

हमारे देश ने उच्च शिक्षा को माध्यमिक की जगह तरजीह दी जिससे एक विश्वस्तरीय शिक्षित अभिजात वर्ग पैदा हुआ। इसके प्रमुख तकनीकी संस्थान और बिजनेस स्कूल सिलिकॉन वैली के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और बेंगलूरु में वैश्विक क्षमता केंद्रों को शक्ति देने वाले इंजीनियरों की आपूर्ति करते हैं। लेकिन 1.4 अरब लोगों की अर्थव्यवस्था कुछ लाख टेक पेशेवरों के सहारे ऊपरी-मध्य-आय का दर्जा हासिल नहीं कर सकती। अरबों डॉलर भौतिक अधोसंरचना में लगाए जा रहे हैं वहीं बुनियादी शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपेक्षित पड़े हैं।

यदि भारत अपने बहुचर्चित जनांकिकीय लाभांश को एक टिक-टिक करते टाइम बम से आर्थिक इंजन में बदलना चाहता है तो उसे दिशा में भारी बदलाव करना होगा। सबसे पहले, सार्वजनिक वित्तपोषण को आक्रामक रूप से शुरुआती सालों में बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर केंद्रित करना होगा। दूसरा, व्यावसायिक प्रशिक्षण को सीधे स्कूल चक्र में एकीकृत करना होगा, जिससे शिक्षा का पैमाना रोजगार-योग्यता पर स्थानांतरित हो। तीसरा, राज्य को उद्योगों और प्रशिक्षण केंद्रों के बीच गहरी संस्थागत साझेदारी बनानी चाहिए, पाठ्यक्रम को गतिशील रूप से अद्यतन करते हुए। ये न्यूनतम कदम हैं। लेकिन ये विचार पहले से ही जाने-पहचाने हैं और विशेषज्ञों द्वारा कई बार व्यक्त किए जा चुके हैं। सवाल यह है कि क्या हम इन्हें परिणाम और जवाबदेही के साथ लागू करने के लिए पर्याप्त गंभीर हैं?

-धनंजय राजौरा

नाबालिग आरोपी ने ही की थी प्रियांशु की हत्या

पाउच मंगवाने की बात पर हुआ विवाद, चाकू से गले पर कर दिया वार

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले के ग्राम नांदनी में मिले 10 वर्षीय बालक के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बालक की हत्या एक नाबालिग ने ही की थी, जिसने पहले तो बालक से गुटखा मंगवाया। गुटखा लाने के बाद जब बालक ने उससे दोबारा ऐसा न करने से मना किया तो दोनो में विवाद हो गया और नाबालिग ने चाकू से गले पर वार कर दिया। पुलिस ने इस घटना का कुछ ही घंटों में पर्दाफाश करते हुए आगामी कार्रवाई की।

जानकारी के अनुसार 16 जुलाई को ग्राम नांदनी निवासी 10 वर्षीय बालक के अपहरण होने की सूचना प्राप्त होने पर थाना कालापीपल पुलिस द्वारा तत्काल अपराध दर्ज कर उसकी तलाश प्रारंभ की गई। लेकिन शुक्रवार सुबह बालक का शव ग्राम के समीप स्थित एमपीईबी के खंडहर में बरामद हुआ। जैसे ही शव मिला गांव में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। हर कोई प्रियांशु के हत्यारों को पकड़ने और कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगा।

पुलिस ने दिखाई तत्परता, मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी- घटना को गंभीरता से लेते हुए मौके पर एसपी प्रियंका शुक्ला, एएसपी घनश्याम मालवीय सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और लोगो से पूछताछ कर सबूत जुटाए। साथ ही स्थानीय पुलिस टीम को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यही नहीं मौके पर डाग स्क्वॉड, एफएसएल अधिकारी एवं फिंगर प्रिंट टीम के द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए गए। नतीजन घटना का खुलासा हो गया और आरोपी भी पुलिस गिरफ्त में आ गया।

ऐसे सुलझी गुत्थी- पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि बालक अंतिम बार यही अपने साथियों के साथ खेल रहा था। जब पुलिस ने अंतिम बार प्रियांशु के साथ देखे गए बालको से पूछताछ की तो इस काम घटना को अंजाम देने वाले आरोपी का नाम सामने आया। प्रारंभिक पूछताछ में नाबालिग बालक ने बताया कि उसने मृतक बालक को राजश्री पाउच लाने के लिए कहा था। मृतक द्वारा पाउच लाकर देने के बाद उसने उससे ऐसी वस्तुएँ भविष्य में न मंगवाने की बात कही। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद मृतक बालक डरकर एमपीईबी के खंडहर की ओर भाग गया, जहां उसका नाबालिग आरोपी से ने पीछा कर बलपूर्वक पकडकर गुस्से में आकर अपने पास रखे चाकू से मृतक बालक के गले पर वार कर हत्या कर दी। जिसके बताए अनुसार पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार एवं अन्य साक्ष्यों के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई।

इनकी रही सराहनीय भूमिका- उक्त सराहनीय कार्य मे थाना प्रभारी थाना कालापीपल रवि भण्डारी, उप निरीक्षक मुनेश्वर भगत, उनि सुनीता मेवाडा, प्रआर विवेक गोस्वामी, प्रआर राहुल सिंह, आनंद, विशाल पटेल, प्रआर सतीश, शिवराज पटेल, अमित शर्मा, मुकेश मोर्य, आरक्षक वेदप्रकाश परमार, आरक्षक नयन यादव, आरक्षक रोहित वर्मा, रवि कारपेंटर, संजय जावरिया, प्रतीकसिंह चोहान, अर्जुन, सतीश, शैलेंद्र, आशीष, महिला आरक्षक नीलम परमार, सेनिक राम सिंह की मुख्य भूमिका रही।

रसायनों से रिश्ता तोड़कर जैविक-प्राकृतिक खेती से लिखी समृद्धि की नई इबारत

ग्वालियर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। वर्तमान दौर में जब कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा प्रतिकूल प्रभाव बड़ी समस्या बन गया है। ऐसे समय में ग्वालियर जिले के ग्राम देवरा के प्रगतिशील किसान श्री विजेंद्र रावत जैविक एवं प्राकृतिक खेती की मिसाल बनकर उभरे हैं। उन्होंने अपनी खेती को पूरी तरह रसायन मुक्त बना दिया है। जैविक प्रमाणन, मूल्य संवर्धन और बेहतर विपणन को अपनाकर बृजेन्द्र रावत ने यह साबित कर दिया कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने का भी प्रभावी माध्यम है। आज वे अनेक किसानों को टिकाऊ, लाभकारी और स्वस्थ कृषि प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

दिल की बीमारी से निकला जैविक खेती का रास्ता - वर्ष 2002 से खेती कर रहे श्री विजेंद्र रावत प्रारंभिक वर्षों में पारंपरिक रासायनिक खेती करते थे। वर्ष 2016 में हृदय संबंधी गंभीर बीमारी के उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें रासायनिक कृषि में प्रयुक्त हानिकारक रसायनों से दूर रहने की सलाह दी। इस सलाह ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने अपनी लगभग 20 बीघा कृषि भूमि पर रासायनिक खेती त्यागकर पूरी तरह जैविक एवं प्राकृतिक खेती अपनाने का निर्णय लिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा।

वैल्यू एडीशन से बढ़ गई आमदनी - कृषक श्री बृजेन्द्र रावत की सफलता केवल जैविक उत्पादन तक सीमित नहीं है। उन्होंने खेती में मूल्य संवर्धन (वैल्यू एडिशन) को भी अपनाया। वे गेहूँ को सीधे बेचने के बजाय उसका आटा और दलिया तैयार कर उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं। इससे उनके उत्पादों का मूल्य बढ़ा और उन्हें सामान्य बाजार की तुलना में अधिक लाभ मिलने लगा।

नल जल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक दिवसीय जनपद स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह के मार्गदर्शन में एक दिवसीय जनपद स्तरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं नल जल योजना संबंधी कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत के सभाकक्ष में किया गया।

कार्यशाला में संयुक्त कलेक्टर श्रीमती विशाखा देशमुख ने सभी सरपंचों, सचिवों और रोजगार सहायकों से कहा कि वे आपसी समन्वय के साथ इन दोनों महत्वपूर्ण नियमों को अपने-अपने ग्रामों में शत-प्रतिशत लागू करें, जिससे देवास जिला ग्रामीण विकास और स्वच्छता के मामले में एक मिसाल बन सके। कार्यशाला के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं पंचायत स्तर के कर्मचारियों ने अपनी शंकाओं का समाधान किया और सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि वे 2026 के इन नवीन नियमों को धरातल पर उतारने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे।

अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ श्री श्याम सुंदर सिंह ने %ग्रामीण नल जल योजना के संचालन, संधारण एवं प्रबंधन नियम 2026% के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की टंकियों और पाइप लाइनों का रखरखाव स्थानीय स्तर पर मुस्तैदी से होना चाहिए ताकि हर नागरिक को नियमित पेयजल मिल सके। उन्होंने इसके वित्तीय प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी को अनिवार्य बताया।

लक्ष्मी नगर क्षेत्र में मिला युवक का शव, परिजनों के अनुसार काम पर जाने निकला था फिर नहीं लौटा

शाजापुर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर के लक्ष्मी नगर क्षेत्र में शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे भाजपा कार्यालय के आगे सड़क पर एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मृतक की पहचान नितिन (25) पिता बंसीलाल मालवीय निवासी टंकी चौराहा के रूप में हुई है। परिवार मूल रूप से आगर जिले का रहने वाला है और वर्तमान में शाजापुर के टंकी चौराहा क्षेत्र में किराए के मकान में रहता है। नितिन मजदूरी करता था। उसका विवाह वर्ष 2021 में हुआ था और उसके दो छोटे बच्चे हैं। परिजनों ने पूछताछ में बताया कि करीब चार महीने पहले नितिन की पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद से वह मानसिक तनाव में रहने लगा था और शराब का अधिक सेवन करने लगा था। मृतक के पिता बंसीलाल मालवीय ने बताया कि नितिन काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। जिस स्थान पर उसका शव मिला उसके पास ही उसके मौसेरे भाई का किराए का मकान है। दोनों साथ में मजदूरी करते थे। कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला ने बताया कि युवक के शरीर पर किसी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। मौत के वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

नातरा विवाद में किसान की टापरी फूंकी, गाय की भी हुई मौत

घटनास्थलसे मिला धमकी भरा पत्र, 58 लाख रुपए की मांग

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले के ग्राम सिंगार चोरी में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात नातरा विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। अज्ञात लोगों ने एक किसान की टापरी में आग लगा दी, जिससे वहां बंधी एक गाय की जलकर मौत हो गई। आग में भूसा, कंडे और अन्य घरेलू सामान भी जलकर राख हो गया। घटना के बाद मौके से एक धमकी भरा पत्र भी मिला है, जिसमें 58 लाख रुपए की नातरा राशि दिलाने की मांग की गई है।

जानकारी के अनुसार ग्राम सिंगार चोरी निवासी देवकरण गुर्जर और राजस्थान के झालावाड़ जिले के ग्राम सुलिया चौकी निवासी गोविंद गुर्जर के बीच लंबे समय से नातरा राशि को लेकर विवाद चल रहा है। इस मामले में कई बार पंचायत भी हो चुकी है। आरोप है कि गोविंद गुर्जर ने देवकरण से 58 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन राशि नहीं मिलने पर गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई थी। ग्रामीणों के अनुसार आग लगाने वाले टापरी में एक पत्र छोड़ गए। इसमें गांव के पटेल और सरपंच से देवकरण गुर्जर से 58 लाख रुपए की नातरा राशि दिलाने की बात लिखी गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जब तक राशि नहीं मिलेगी, तब तक गांव के लोगों को इसी तरह नुकसान पहुंचाया जाएगा।

गाय की मौत, किसान को नुकसान- आगजनी में किसान रामेश्वर गुर्जर की टापरी पूरी तरह जल गई। टापरी में बंधी एक बुजुर्ग गाय की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। भूसा, कंडे और अन्य जरूरी सामान भी आग की भेंट चढ़ गया, जिससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। पीड़ित किसान रामेश्वर गुर्जर ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि नातरा विवाद के चलते उनकी टापरी को निशाना बनाया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पत्र की भी जांच की जा रही है।

देवास जिले के संपूर्ण क्षेत्र के लिए कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए जन सामान्य के हित/जानमाल की सुरक्षा तथा लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए देवास जिले के संपूर्ण क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये है।

जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि का आयोजन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य पक्ष सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना डी.जे./ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा The Noise Pollution (Regulation and Control) Rule 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड, रास्ता हाईवे, आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रुकावट उत्पन्न नही करेंगे या किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप्प एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आमजन की भावना भड़काने वाले अथवा किसी को बुरा लगने या आहत करने वाले व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज/चित्र/कमेंट/बैनर/पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा/प्रदर्शित नहीं करेगा।

जिले में शांति-कानून व्यवस्था तथा आमजन की सुरक्षा व सुविधा में संलग्न और शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों/पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह निर्देश लागू नहीं होंगे। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाएं रखने हेतु इन्हें आवश्यक वैधानिक छूट प्राप्त होगी। आवश्यक होने पर जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारीगण अपने-अपने क्षेत्र में संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) से परामर्श कर आवश्यक प्रतिबंध/शर्तों पर किसी कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत रहेंगे।

विद्यार्थियों को दिलाई नशा मुक्ति की शपथ

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और उन्हें एक स्वस्थ जीवन की राह दिखाने के उद्देश्य से, संस्कार पब्लिक एकेडमी में नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को नशे के दुष्परिणाम बताते हुए इससे दूर रहने और त्यागने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रवि सिंह चौधरी, विशेष अतिथि अर्जुन सिंह राजपूत ने बच्चों को संबोधित करते हुए जीवन में अनुशासन और नैतिक मूल्यों के महत्व को समझाया। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे स्वयं को हर प्रकार के नशे और बुरी आदतों से दूर रखें तथा समाज में भी इसके खिलाफ जागरूकता फैलाएं। इस दौरान सभी विद्यार्थियों और स्टाफ को नशे से हमेशा दूर रहने तथा एक नशामुक्त और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। साथ ही इस तरह के आयोजन को लेकर पुलिस अधिकारियों ने स्कूल प्रशासन की सराहना भी की। कार्यक्रम में संस्कार विद्यालय के प्रबंधक भोजराज कारपेंटर, मुकेश वर्मा, राकेश परमार, प्रधान अध्यापिका एवं शिक्षक गण और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। वहीं पुलिस विभाग की ओर से एएसआई सैयद मोहम्मद अली, प्रधान आरक्षक रविशंकर चौधरी, सैनिक अर्जुन सिंह राजपूत, रतन सिंह आदि उपस्थित थे।

(मेधावी विद्यार्थियों के लिए जिला प्रशासन की अनूठी पहल) मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगी जेईई-नीट की निःशुल्क कोचिंग, तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल का किया वितरण

कलेक्टर श्री सिंह ने कोचिंग से एक कदम आगे रहकर स्ट्रेटजी बनाने की दी सलाह

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठी और अनुकरणीय पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत कक्षा 10वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जिले के मेधावी विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान फिजिक्स वाला फाउंडेशन के सहयोग से निःशुल्क जेईई और नीट की तैयारी कराई जा रही है। कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह की उपस्थिति में खेडापति होटल में कार्यक्रम का आयोजन कर कक्षा 10वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 136 मेधावी छात्र-छात्राओं को जेईई और नीट की तैयारी के लिए निःशुल्क स्टडी मटेरियल का वितरण किया गया। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जिला प्रशासन और फिजिक्स वाला फाउंडेशन द्वारा अत्याधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। छात्रों को नियमित ऑनलाइन लाइव क्लासेस के साथ-साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे बच्चे अपनी सुविधानुसार कभी भी कठिन विषयों को दोबारा समझ सकेंगे और उनका रिवीजन कर सकेंगे।

कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनका हौसला बढाते हुए कहा कि जिले की प्रतिभाओं को संसाधनों की कमी के कारण पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। यह पहल ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के होनहार बच्चों के सपनों को उड़ान देने का काम करेगी। जिला प्रशासन इन विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य और बेहतर परिणाम के लिए हर संभव मदद उपलब्ध कराता रहेगा।

कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने कहा कि यह सब आपकी कड़ी मेहनत का ही परिणाम है। जब आप सच्चे मन से परिश्रम करते हैं, तो बिना मांगे ही कोई न कोई माध्यम आपकी सहायता के लिए आगे आ जाता है। आप सभी अत्यधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, इसीलिए आपके लिए इस ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। यह आप सभी के लिए एक बेहतरीन अवसर है, आप सभी को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।

कलेक्टर श्री सिंह ने छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए जागरूक करते हुए कहा कि यदि आप नीट और जेईई के माध्यम से देश के टॉप कॉलेजों में जाने की इच्छा रखते हैं, तो आपको सामान्य से बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। टॉप कॉलेजों में सीट पाने के लिए ऑल इंडिया लेवल पर कड़ा कंपटीशन है। आपका परफॉर्मेंस भी उसी ऊंचे स्तर का होना चाहिए। आपको इसी राष्ट्रीय मापदंड और पैमाने को ध्यान में रखकर दिन-रात पढ़ाई करनी होगी।

कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि यह 2 साल आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फेज हैं, जो आपका पूरा भविष्य निर्धारित करेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से ऑल इंडिया लेवल पर टॉप 5000 रैंक में आने का लक्ष्य रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश में लाखों बच्चे जेईई और नीट की परीक्षा देते हैं। आपका प्रयास देश के शीर्ष आईआईटी और एम्स जैसे संस्थानों में जाने का होना चाहिए। इन प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यार्थी नाम मात्र की फीस देकर बड़ी-बड़ी ग्लोबल कंपनियों में जाते हैं। इससे न केवल आपका बल्कि आपके पूरे परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर हमेशा के लिए बदल जाएगा।

कलेक्टर ने कहा कि कोचिंग में जो चैप्टर पढ़ाया जाने वाला हो, उसे छात्र एक बार खुद पहले से पढ़कर जाएं। अगर आप 10 से 20 प्रतिशत चैप्टर पहले खुद समझ लेंगे, तो कोचिंग में पढ़ते समय आपको 80 से 90 प्रतिशत चीजें तुरंत समझ में आ जाएंगी। देश के टॉप कॉलेजों में जगह बनाने के लिए केवल कोचिंग पर निर्भर न रहें। प्रतिदिन कम से कम 10 घंटे की कड़ी सेल्फ स्टडी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगले 2 साल के लिए अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए हर प्रकार के सोशल नेटवर्क से पूरी तरह बाहर रहने की कोशिश करें।

कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि बड़े शहरों के बच्चों के पास संसाधन अधिक हैं और हर जिले में आपके जैसे ही होनहार छात्र तैयारी कर रहे हैं। आपका असली कंपटीशन उन बड़े शहरों के बच्चों के साथ है। इसलिए आपको अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के स्तर को लगातार बढ़ाना होगा और बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। उन्होंने छात्रों को निरंतरता का महत्व समझाते हुए सचेत किया कि अगर आप पढ़ाई में एक बार पीछे छूट गए, तो वापस कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने सभी मेधावी छात्रों को हर साप्ताहिक और मासिक टेस्ट में अनिवार्य रूप से शामिल होने और उसमें सर्वश्रेष्ठ परफॉर्म करने के लिए कहा।

कलेक्टर श्री सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित फिजिक्स वाला के शिक्षकों को से कहा कि वे बच्चों को पूरी लगन से पढ़ाएं और हर एक बच्चे की प्रोग्रेस पर विशेष फोकस व ध्यान दें। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा स्वयं हर महीने समीक्षा की जायेगी। कलेक्टर श्री सिंह ने छात्रों को इस अवसर की कीमत समझाते हुए कहा कि आज देश भर में लाखों बच्चे इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए भारी-भरकम फीस और लाखों रुपए खर्च करते हैं। आपको यह विश्वस्तरीय अपॉर्चुनिटी आपके घर बैठे बिल्कुल निःशुल्क मिल रही है। यह मौका सबको नहीं मिलता, इसलिए इस विशेष सुविधा का पूरा लाभ उठाएं, पूरी ताकत झोंक दें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं।

इस अवसर पर फिजिक्स वाला संस्थान के प्रतिनिधि श्री रचित त्रिपाठी ने छात्रों को डिजिटल लर्निंग का पूरा ढांचा समझाया। उन्होंने जानकारी दी कि क्लासेस किस प्रकार संचालित की जाएंगी। छात्र मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लाइव क्लासेस से कैसे जुड़ेंगे, टेस्ट कैसे देंगे और स्टडी मटेरियल का उपयोग कैसे करेंगे, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने बताया कि छात्रों को नियमित ऑनलाइन लाइव क्लास के साथ-साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सुविधा भी मिलेगी, जिससे वे किसी भी टॉपिक का कभी भी रिवीजन कर सकेंगे।

कार्यक्रम में जिले की होनहार छात्राओं ने भी अपने अनुभव साझा किए और इस पहल को आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए मददगार बताया। 10वीं कक्षा में 98 प्रतिशत अंक प्राप्त कर मध्य प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 10वां स्थान पाने वाली उत्कृष्ट विद्यालय देवास की छात्रा पलक नामदेव ने बताया कि बिना किसी कोचिंग के केवल नियमित स्कूल जाकर और सेल्फ स्टडी से यह मुकाम हासिल किया है। हर बच्चा बड़ी कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। जिला प्रशासन की इस निःशुल्क कोचिंग सुविधा से हम जैसे बच्चों को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। कक्षा 10वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली खातेगांव उत्कृष्ट स्कूल की छात्रा ऊषा जायसवाल ने कहा, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सटीक स्टडी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी।

कोबरा के डंसने से हुई बुजुर्ग की मौत, परिजनों ने भी कर दी सांप की हत्या

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला अस्पताल में ब्लैक कोबरा सांप के डंसने से राजगढ़ जिले के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन सांप को मारकर उसे एक झोले में बंद कर सीधे अस्पताल ले आए। अस्पताल परिसर में मृत सांप को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई और यह घटना दिनभर चर्चा का विषय बनी रही।

राजगढ़ जिले के झाड़ पिपलिया गांव के रहने वाले लक्ष्मीनारायण (62) शुक्रवार सुबह अपने घर में पूजा-पाठ करने के बाद कंघी कर रहे थे। इसी दौरान वहां छुपकर बैठे एक जहरीले ब्लैक कोबरा सांप ने अचानक उनके पैर के अंगूठे पर डंस लिया। सांप के काटते ही लक्ष्मीनारायण की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। बुजुर्ग को सांप काटने के बाद परिजनों ने उस कोबरा को ढूंढकर मार डाला। इसके बाद वे लक्ष्मीनारायण और मृत सांप दोनों को एक ही गाड़ी में रखकर इलाज के लिए शाजापुर जिला अस्पताल भागे। हालांकि अस्पताल पहुंचने में काफी देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने जांच के बाद बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई प्रेम सिंह ने बताया कि वे डॉक्टरों को दिखाने के लिए ही सांप को झोले में साथ लाए थे। अस्पताल की पुलिस चौकी पर तैनात प्रधान आरक्षक पदम सिंह ने बताया कि अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है।

सतवास में जिला प्रशासन ने कार्रवाई कर 12 निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म बेचने वाली कान्हा कलेक्शन दुकान को किया सील

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म को लेकर मिल रही शिकायतों पर शुक्रवार को जिला प्रशासन ने सतवास में बड़ी कार्रवाई करते हुए कान्हा कलेक्शन दुकान को सील किया हैं। कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर जिला परियोजना समन्वय अधिकारी अजय मिश्रा के नेतृत्व में शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान सतवास तहसीलदार अवधेश कुमार यादव और थाना प्रभारी दिलीप पुरी मौजूद रहे। टीम ने दुकान के साथ कुछ निजी स्कूलों का भी निरीक्षण किया। जांच के दौरान दुकानदार ने स्वीकार किया कि उसकी दुकान पर 12 निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म उपलब्ध है, लेकिन वह ऐसे कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका, जिनसे यह स्पष्ट हो सके कि वह इन स्कूलों की यूनिफॉर्म किस आधार पर बेच रहा था। कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन और यूनिफॉर्म बिक्री में एकाधिकार की शिकायत को देखते हुए प्रशासन ने दुकान को सील कर दिया। संयुक्त टीम ने निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म और पुस्तकों की व्यवस्था की भी जांच की।

गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा तहत विद्यार्थियों ने किया सांदीपनि विद्यालय की आधुनिक प्रयोगशालाओं का भ्रमण

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। गुरु पूर्णिमा पखवाड़े के अंतर्गत स्थानीय सांदीपनि विद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक व रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं, हाईस्कूल खेड़ा के विद्यार्थियों और शिक्षक गणों ने सांदीपनि विद्यालय बदनावर का शैक्षणिक भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विद्यालय की अत्याधुनिक जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रोबोटिक लैब का बारीकी से अवलोकन किया। इसके साथ ही उन्होंने संगीत कक्षा और सर्वसुविधायुक्त पुस्तकालय को भी देखा। आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक उपकरणों और उच्चस्तरीय शैक्षणिक वातावरण को देखकर विद्यार्थी और शिक्षक बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने इस अनुभव को लेकर अपने सकारात्मक विचार भी व्यक्त किए।

पखवाड़े के तहत विद्यालय परिसर में एक भव्य भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह राठौर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्राचार्य रियाजुद्दीन शेख ने मुख्य अतिथि का आत्मीय स्वागत किया। इस प्रतियोगिता में कुल 42 छात्र-छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और अपने विचार रखे। कड़े मुकाबले के बीच निर्णायकों द्वारा परिणामों की घोषणा की गई जिसमे प्रथम स्थान - स्वाति पिता इंद्रजीत नाथावत, कक्षा 11वीं, द्वितीय स्थान- रिया शर्मा, कक्षा 11वीं, तृतीय स्थान- किंजल पाटीदार, कक्षा 12वीं रही। प्रतियोगिता में निर्णायक भूमिका श्रीमती अनीता राठौर, श्रीमती चंदा प्रजापत एवं श्रीमती आयुषी पाटीदार ने निभाई।

कार्यक्रम के दौरान शिक्षक-शिक्षिकाएं श्रीमती रेणु पाटीदार, वैभव चौरडिया, शुभम उपाध्याय और जितेंद्र रावल विशेष रूप से उपस्थित रहे। जिन्होंने छात्र-छात्राओं का मार्गदर्शन करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। समारोह का संचालन प्रदीप पांडेय ने किया तथा कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथियों, शिक्षकों व विद्यार्थियों का आभार श्रीमती रानू पाटीदार ने व्यक्त किया।

स्वर्गीय गहलोत की स्मृति में होगा निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन

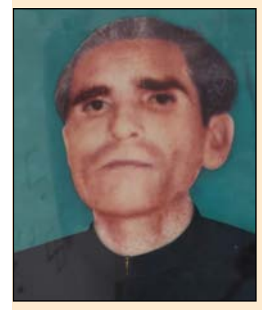

अकोदिया/ अमर सिंह मेवाडा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। अकोदिया शुजालपुर सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय संत हिरदाराम नगर सेवा सदन नेत्र जांच केंद्र शुजालपुर मंडी के सहयोग से समाजसेवी श्री खाटू श्याम सेना ट्रस्ट शाजापुर जिला अध्यक्ष सुशील कुमार गेहलोत के पूज्य पिताजी स्वर्गीय देवेंद्र कुमार जी गेहलोत की स्मृति में निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन 30 जुलाई 2026 गुरुवार को सेवा सदन नेत्र जांच केंद्र सरकारी अस्पताल के सामने शुजालपुर मंडी में आयोजित होगा सेवा सदन केंद्र प्रभारी खुशीराम आचार्य ने बताया कि समाज सेवी डॉक्टर सुशील कुमार गेहलोत द्वारा प्रतिवर्ष उनके पूज्य पिताजी के स्मृति में निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जाता है शिविर में आंखों की जांच के पश्चात मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित मरीज को बस द्वारा संत हिरदाराम नगर ले जाया जाएगा।

जिला न्यायालय परिसर में पंच-ज अभियान के तहत पौधारोपण संपन्न

आगर-मालवा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री डी.एस. चौहान के निर्देशानुसार पंच-ज अभियान के तहत जिला न्यायालय परिसर आगर-मालवा में फलदार एवं फूलदार पौधों का रोपण किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री डी.एस. चौहान ने कहा कि पंच-ज अभियान का मुख्य उद्देश्य जल, जंगल, जमीन, एवं जन, आदि का संरक्षण करना है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रत्येक नागरिक को वृक्षारोपण कर उसके संरक्षण में सहभागिता निभानी चाहिए।न्यायालय परिसर में रोपित किए गए पौधों की देखरेख एवं संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु उन्होंने न्यायालयीन कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए।

इस अवसर पर द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री मधुसूदन जंघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अरुण सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अश्विनी सिंह, व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती मोनिका यादव, व्यवहार न्यायाधीश सुश्री प्रियंका चौहान,सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी कर्मचारीगण उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए अधिकाधिक पौधे लगाने तथा उन्हें सुरक्षित रखने का संदेश दिया।

दस लाख की लागत से नगर होगा बदनावर हाईटेक और सुरक्षित

हर नागरिक की सुरक्षा हमारा सर्वोपरि संकल्प - मीना शेखर यादव

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर विकास, जन-सरोकार और आधुनिक बदलाव की दिशा में काम करते हुए नगर परिषद बदनावर ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की है। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य, सुदृढ़ और बेहद आधुनिक बनाने के लिए नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मीना शेखर यादव की विशेष सक्रियता और प्रयासों से पूरे शहर को %तीसरी आंख% की सुरक्षा मिलने जा रही है। सांसद निधि से दस लाख की लागत से शहर के प्रमुख स्थानों अत्याधुनिक वॉइस ऑडियो युक्त नाइट विज़न सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिसमे प्रथम चरण में शहर के प्रमुख स्थानों पर 50 अत्याधुनिक 4 मेगापिक्सल वॉइस ऑडियो युक्त नाइट विज़न सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का गरिमामय व विधिवत शुभारंभ शुक्रवार को नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मीना शेखर यादव द्वारा किया गया।

यह महत्वपूर्ण और जनोपयोगी सौगात केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री व धार-महू लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर की सांसद निधि से मिली है, जिसे धरातल पर उतारने और त्वरित गति से क्रियान्वित करवाने में नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती यादव ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के धरातल पर आने से बदनावर अब बेहद सुरक्षित, स्मार्ट और हाईटेक शहरों की श्रेणी में शामिल हो रहा है।

श्रीमती मीना शेखर यादव की मंशा के अनुरूप योजना के पहले चरण में उन सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है जहाँ लोगों की आवाजाही सबसे अधिक होती है जिसमे बड़ी चौपाटी, बस स्टैंड, शीतला माता बस स्टैंड, निचलावास, मंडी रोड, जवाहर मार्ग, मालीपुरा सहित विभिन्न वार्डों के प्रमुख चौराहे। साथ ही नगर की बेटियों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सिविल अस्पताल परिसर, शासकीय कन्या विद्यालय के साथ-साथ बैजनाथ महादेव मंदिर, माँ एकवीरा मंदिर एवं चिंतामणि गणेश मंदिर परिसर को भी इस सुरक्षा कवच से जोड़ा गया है।

अध्यक्ष श्रीमती यादव के नेतृत्व में सुरक्षा तंत्र को बेहद चाक-चौबंद रूप दिया गया है। इसके तहत दो विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं जिसमे प्रथम कंट्रोल रूम नगर परिषद कार्यालय एवं द्वितीय कंट्रोल रूम पुलिस थाना परिसर में स्थापित किया जाएगा। ये कैमरे वाई-फाई और ऑनलाइन नेटवर्क से लैस हैं, जिससे सुरक्षा अधिकारी सीधे अपने मोबाइल पर भी लाइव फीड देख सकेंगे। इससे नगर में शांति, सुरक्षा और भाईचारे का माहौल और अधिक मजबूत होगा।

शुभारम्भ अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मीना शेखर यादव ने कहा की - ÷बदनावर हमारा परिवार है, और परिवार के हर सदस्य– विशेषकर हमारी माताओं, बहनों, बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। लंबे समय से शहर को एक आधुनिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता थी। सांसद निधि के सहयोग से आज यह सपना सच हो रहा है। ये हाईटेक कैमरे न केवल अपराधों पर अंकुश लगाएंगे, बल्कि यातायात को सुगम बनाने और नागरिकों में सुरक्षा व विश्वास का भाव जगाने में मील का पत्थर साबित होंगे। बदनावर को सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित बनाने का हमारा यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा।

शुभारम्भ अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी विकास डावर, नगर परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्रसिंह पवार, अध्यक्ष प्रतिनिधि शेखर यादव, पार्षद सुखराम देवदा, डॉ. संतोष चौहान, चेतन नागल सहित अनेक गणमान्य नागरिक और हर्षित वार्डवासी उपस्थित थे। इस बेहतरीन पहल के उपस्थितजन ने लिए नगर परिषद की पूरी टीम और विशेष रूप से अध्यक्ष श्रीमती यादव के प्रयासों की प्रशंसा की।

अल्प वर्षा की मारः बदनावर तहसील सहित कठोडिया छोटा में सोयाबीन की फसल संकट में, किसान चिंतित

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। बदनावर तहसील क्षेत्र सहित ग्रामीण अंचलों में मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। क्षेत्र के ग्राम कठोडिया छोटा सहित आसपास के कई गांवों में अल्प वर्षा (कम बारिश) के कारण सोयाबीन की फसल बुरी तरह प्रभावित हो रही है। लंबे समय से बारिश न होने के कारण खेतों में खड़ी फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं।

फसलों पर पड़ रहा है विपरीत असर- किसानों के मुताबिक, इस बार सीजन की शुरुआत में बोनी के समय तो बारिश ठीक हुई थी, लेकिन अब जब फसल को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी से बादलों ने मुंह मोड़ लिया है। तेज धूप और उमस के कारण जमीन की नमी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। क्षेत्र के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक गांव कठोडिया छोटा में फसलों की वृद्धि रुक गई है और पौधे पीले पड़ने लगे हैं।

लागत डूबने का डर- क्षेत्र के पीड़ित किसानों का कहना है कि उन्होंने महंगे दामों पर बीज और खाद खरीदकर बुआई की थी। निंदाई-गुड़ाई में भी काफी खर्च हो चुका है। अगर आगामी एक-दो दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई, तो सोयाबीन की फसल पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा।

राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए तहसील स्तर पर आयोजित हुई विशेष जनसुनवाई

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशन में आमजन की राजस्व संबंधी समस्याओं का त्वरित, प्रभावी एवं स्थानीय स्तर पर निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले की सभी तहसीलों में प्रत्येक शुक्रवार विशेष राजस्व जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय के बजाय तहसील स्तर पर ही बेहतर एवं समयबद्ध सुविधा उपलब्ध कराना है।

कृषि वैज्ञानिको ने खरीफ फसलों के लिए सलाह

आगर-मालवा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कृषि विज्ञान केन्द्र, आगर मालवा के द्वारा बदलते मौसम में सोयाबीन, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का, मूंगफली एवं अन्य खरीफ की फसल को सूखे की स्थिति से बचाने हेतु किसानो को सलाह दी, कि फसल की फव्वारा विधि से सिंचाई का प्रबंधन करें। जिन किसानों ने बीबीएफ मशीन द्वारा बुवाई की है, वो नालियों से सिंचाई कर सकते है। यदि सोयाबीन की फसल की 15-20 दिन की अवस्था में है, तो डोरा एवं कुरपा चलाकर खरपतवार का नियंत्रण करें एवं निदाई के समय खरपतवारों का पलेवार/बिछावन के रूप में प्रयोग करें। विकल्प के रूप में सोयाबीन के उगने के बाद खेत में 5 टन/हेक्टेयर भूसा फैलाकर नमी को उड़ने से बचा सकते है। नमी की कमी की स्थिति में पौटेशियम नाईट्रेट 1 प्रतिशत अथवा मैग्नीशियम कार्बोनेट 5 प्रतिशत का छिड़काव किया जा सकता हैं। सोयाबीन की फसल में प्रारम्भिक 30-45 दिन के दौरान सूखे वाली स्थिति होने पर कैल्शियम जनित लोहा तत्व की कमी के लक्षण उपरी पत्ती का पीलापन के रूप में दिखाई देता है, इसके लिए जिंक सल्फेट 5 ग्राम/लीटर पानी .आयरन सल्फेट 10 ग्राम/लीटर पानी को बुझे चूने 2 ग्राम/लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करें।वास्तविक स्थिति के आंकलन हेतु खेत की नियमित निगरानी करें।

यात्री हितों को मिलेगी नई मजबूती, यात्री विकास एवं सुझाव मंच ने तीन उपाध्यक्ष किए मनोनीत

सुमेर सिंह सिसोदिया, राजा कर्नावट एवं शंकर (पप्पू) प्रजापत को सौंपी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

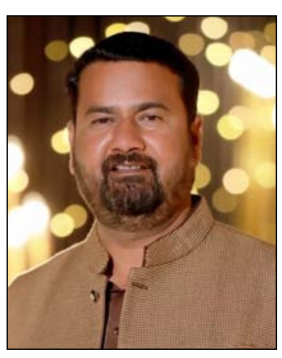

नागदा/ राजेश सकलेचा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। यात्रियों की समस्याओं के समाधान, रेलवे सुविधाओं के विस्तार तथा जनहित से जुड़े विषयों को संबंधित विभागों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यरत यात्री विकास एवं सुझाव मंच ने संगठन का विस्तार करते हुए सुमेर सिंह सिसोदिया, राजा कर्नावट एवं शंकर (पप्पू) प्रजापत को मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया है।

मंच के संस्थापक अध्यक्ष एवं संचालक राजेश सकलेचा ने तीनों नव-मनोनीत उपाध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मंच का ध्येय वाक्य ÷आपका सुझाव, हमारा संकल्प÷ केवल एक नारा नहीं, बल्कि जनसेवा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि तीनों पदाधिकारी अपने अनुभव, सामाजिक सक्रियता एवं जनसंपर्क के माध्यम से मंच की गतिविधियों को नई दिशा देंगे तथा यात्रियों की समस्याओं, रेलवे सुविधाओं के विस्तार और जनहित से जुड़े विषयों को संबंधित विभागों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने कहा कि मंच निरंतर यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि, नई रेल सेवाओं के संबंध में सुझाव, स्टेशन विकास, स्वच्छता, सुरक्षा तथा अन्य यात्री सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर रचनात्मक रूप से कार्य कर रहा है। संगठन का विस्तार इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे जनभागीदारी और अधिक सशक्त होगी तथा यात्री हितों से जुड़े विषयों को संगठित रूप से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

इस अवसर पर मंच के परामर्शदाता वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सनोलिया, समाजसेवी पंकज मारू एवं अधिवक्ता एस.के. साहु, संयोजक चेतन यादव, सुनील त्रिवेदी एवं भवानी सिंह देवड़ा, अध्यक्ष नितिन जैन (उन्हेल), सचिव रवि चौहान (पिपलोदा), कोषाध्यक्ष दीपक जैन, प्रमोद कोठारी, सी.एम. अतुल, डॉ. सुरेन्द्र मीणा, गौतम लश्करी, जीवनलाल जैन, दिनेश सेठिया, प्रकाश मालपानी, अर्जुन राजोरिया, दिनेश सोलंकी, निलेश जैन सोलंकी, सुनील सकलेचा, अनुज नाहर, अमित बम, मनीष भण्डारी, अनिल शर्मा, डॉ. सी.एन. शुक्ला, हिमांशु ओझा एवं भूपेन्द्र चौहान सहित मंच के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने तीनों नव-नियुक्त उपाध्यक्षों का स्वागत करते हुए उनके सफल एवं जनहितकारी कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।

अ.जा. आयोग के सदस्य रामलाल मालवीय ने मां बगलामुखी देवी मंदिर में दर्शन कर, पूजा-अर्चना की

आगर-मालवा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री रामलाल मालवीय ने शुक्रवार को आगर-मालवा जिले के प्रवास के दौरान जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक आस्था के केंद्र शक्तिपीठ मां पीतांबरा बगलामुखी देवी मंदिर, नलखेड़ा में दर्शन कर पूजा-अर्चना की। उन्होंने प्रदेश एवं जिले वासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना भी की। इस अवसर पर श्री मालवीय ने मंदिर परिसर में विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया तथा नलखेड़ा में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास का निरीक्षण भी किया और विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

आगर-मालवा में नालसा मानव-वन्यजीव संघर्ष योजना पर जागरूकता शिविर संपन्न

आगर-मालवा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। वन विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में गत दिवस नालसा मानव-वन्यजीव संघर्ष योजना विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री डी.एस. चौहान के मार्गदर्शन में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। इस शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अश्विनी सिंह विशेष रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया । तत्पश्चात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अश्विनी सिंह ने प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं, मोटर वाहन अधिनियम तथा वन्यजीव संरक्षण से संबंधित प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अरुण सिंह ने नालसा मानव-वन्यजीव संघर्ष योजना के संबंध में वन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला और आमजन को वन्यजीवों के संरक्षण एवं मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति में नियमानुसार सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। शिविर का संचालन वन रक्षक श्री के पी सिंह झाला ने किया । आभार सुसनेर के रेंजरश्री चंदरसिंह पवार ने व्यक्त किया।

इस अवसर पर उप वन मंडल अधिकारी शाजापुर श्री फतेह सिंह निनामा, रेंजर श्री अशोक सिंह बघेल वन विभाग तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी,कर्मचारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

मल्हारगढ़ में खड़े ट्राले से टकराई कार, ओवरब्रिज निर्माण में देरी पर फिर उठे सवाल

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मल्हारगढ नगर के बस स्टैंड स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार देर रात करीब 2 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार जीजे 03 एच आर 5988 पीछे से सड़क किनारे खड़े ट्राले में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। शुक्रवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त वाहन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। मामले में पुलिस थाना मल्हारगढ को जनाकारी नही थी। घायलों के नाम की भी जानकारी नही । थाने पर तैनात आरक्षक का कहना था कि कोई रिपोर्ट लिखाने आएगा तब सब पता चलेगा। वही टीआई अनिल रघुवंशी से संपर्क किया। लेकिन उन्होंने काल रिसीव नही की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त वाहन हटवाकर यातायात सुचारु कराया। इस हादसे के बाद एक बार फिर मल्हारगढ़ में लंबे समय से लंबित ओवरब्रिज निर्माण का मुद्दा चर्चा में आ गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि 29 जनवरी को मुख्यमंत्री द्वारा ओवरब्रिज का भूमिपूजन किए जाने के बावजूद अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। आरोप है कि ठेकेदार की ओर से कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, जबकि इस व्यस्त हाईवे पर आए दिन जाम और सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। नगर के दोनों ओर आबादी होने के कारण प्रतिदिन हजारों विद्यार्थी, व्यापारी, किसान और आम नागरिक इस व्यस्त मार्ग को पार करने के लिए मजबूर हैं। वर्षों से ओवरब्रिज की मांग की जा रही है। कई बार स्वीकृति मिलने, बड़े-बड़े होर्डिंग लगने और भूमिपूजन होने के बावजूद निर्माण कार्य धरातल पर शुरू नहीं हो सका। नगरवासियों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से ओवरब्रिज निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने तथा देरी के कारणों को सार्वजनिक करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते निर्माण कार्य शुरू हो जाता, तो ऐसे हादसों की आशंका काफी हद तक कम की जा सकती थी। फिलहाल यह सवाल बना हुआ है कि भूमिपूजन के महीनों बाद भी निर्माण कार्य आखिर शुरू क्यों नहीं हो सका।

सभी छात्रावासों में शत-प्रतिशत सीटों पर विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करें- श्री मालवीय

विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाते समय ही आधार अपडेशन एवं लिंकेज करवाए-अ.जा आयोग

आगर-मालवा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री रामलाल मालवीय ने आगर-मालवा के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार को आयोजित जिला अधिकारियों की बैठक में अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव, एसपी श्री दिलीप कुमार सोनी, एडीएम श्री आरपी वर्मा, जि.पं. सीईओ श्री बी.एस सोलंकी, सभी एसडीएम तथा जिला अधिकारी उपस्थित थे

बैठक में आयोग के सदस्य श्री रामलाल मालवीय ने जिले में संचालित अ.जा. छात्रावासों में निर्धारित सीट, विद्यार्थियों का प्रवेश एवं रिक्त सीटों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि इस सत्र में सभी छात्रावासों में निर्धारित सभी सीटों पर प्रवेश दिलाया जाए। उन्होंने अ.जा. कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शालाओं और घर-घर संपर्क अभियान चलाकर छात्रावासों की सभी सीटों पर विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करें।

आयोग के सदस्य ने अ.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों की संख्या और उन पर की गई कार्यवाही, राहत स्वीकृति आदि की भी जानकारी ली। आयोग के सदस्य श्री मालवीय ने कहा कि अ.जा. वर्ग के विद्यार्थियों की आधार लिंकेज, अपडेशन आदि कारणों से लंबित छात्रवृत्ति का त्वरित भुगतान करवाया जाए।

बैठक में बताया गया कि जिले में अ.जा. अत्याचार निवारण राहत योजना के तहत वर्ष 2025-2026 में 127 प्रकरणों में 93.70 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। राहत स्वीकृति का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत 8 प्रकरणों में 1.65 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। अंतरजातीय विवाह योजना के तहत 8 प्रकरणों में 16 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि भुगतान की गई है।

अ.जा. आयोग के सदस्य श्री मालवीय ने आयोग में लंबित शिकायतों के बारे में एक-एक प्रकरण पर चर्चा कर उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि आयोग को भेजने के लिए लंबित प्रतिवेदन अविलंब भेजे। उन्होंने आयोग से प्रेषित लंबित सभी प्रकरणों में एक सप्तांह में जांच पूरी कर प्रतिवेदन उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए हैं।

बैठक में आयोग के सदस्य श्री मालवीय ने अनुसूचित जाति हितग्राहियों के लिए बस्ती विकास योजना के तहत विद्युतीकरण के लंबित प्रकरणों का निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने तथा सभी स्ववरोजगार योजनाओं मे लक्ष्य से अधिक प्रकरण तैयार कर बैंकों को स्वीकृति हेतु भेजने के निर्देश सभी विभागों को दिए।

कलेक्टर श्रीमती यादव ने आयोग को आश्वस्त किया कि सभी प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही पूर्ण कर, एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन प्रेषित कर दिया जाएगा। जिला संयोजक श्री शेखर उईके ने बैठक के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया और विभागीय प्रगति से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री डा. यादव, प्रधानमंत्री जी के विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार कर रहे है- सांसद

नई सड़को, प्रोजेक्ट के निर्माण में पेड़ पौधों को नुकसान ना हो- सांसद श्री सोलंकी

आगर-मालवा/दैनिक मालवा हेराल्ड। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देश को 2047 तक दुनिया का अग्रणी और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री जी के उक्त संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। यह बात राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री रोडमल नागर ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट कार्यालय आगर में आयोजित जिला स्तरीय विकास समन्वय और निगरानी दिशा समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कही।

बैठक में संसदीय क्षेत्र देवास के सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक आगर श्री मधु गहलोत, विधायक सुसनेर श्री भैरव सिंह बापू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मुन्ना बाई चौहान, कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव, एसपी श्री दिलीप कुमार सोनी, एडीएम श्री आर.पी. वर्मा, जिला अध्यक्ष श्री ओम मालवीय, जिले के सभी जनपदों के अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, नगरीय निकायों के अध्यक्ष, जिला पंचायत सीईओ श्री बी.एस. सोलंकी एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।

सांसद श्री नागर ने कहा कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में आगर जिला भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। हर एक व्क्ति जिस भी क्षेत्र में जहा भी कार्य कर रहे हैं, वे अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करें और जिले, प्रदेश तथा राष्ट्र को सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दें।

देवास क्षेत्र के सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी ने बैठक में कहा कि सभी विभाग यह ध्यान रखें कि किसी भी नए प्रोजेक्ट या निर्माण कार्य की वजह से पेड़-पौधों और पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। सभी विभाग पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दें। बैठक में विधायक श्री मधु गहलोत सहित सभी उपस्थित सदस्यों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

बैठक में कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद श्री नागर ने कहा कि जिले के किसानों को अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण करवाने के लिए प्रेरित किया जाए। मिट्टी परीक्षण के परिणाम के आधार पर खेत की मिट्टी में सुधार करवाने के लिए किसानों को जागरूक किया जाए।

समूह नल जल प्रदाय योजना की प्रगति की समीक्षा में बैठक में निर्देश दिए गए कि मजरों, टोलो और छूटी हुई बसाहटों को भी हर-घर नल से जल प्रदाय योजना में शामिल किया जाए। नल कनेक्शन प्रदान करने का कार्य तेजी से पूर्ण करवाया जाए। जिन 80 गांवों में समूह नल जल प्रदाय योजना से जल आपूर्ति प्रारंभ हो गई है, उनकी सूची समिती सदस्योंय भी दी जाए।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास शहरी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। उपस्थित सदस्यों ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

अंत में कलेक्टर ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए बैठक में प्राप्त सुझावों पर प्रभावी कार्यवाही करने का विश्वास दिलाया।

प्रारंभ में कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव, एसपी श्री दिलीप कुमार सोनी, जिला पंचायत सीईओ श्री बी.एस. सोलंकी एवं एडीएम श्री आर.पी. वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया।

कलेक्टर ने राणापुर क्षेत्र के विद्यालयों एवं छात्रावासों का किया निरीक्षण

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने शुक्रवार को जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं छात्रहित से जुड़े विषयों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्राथमिक विद्यालय खोकड़ी फलिया बन, शासकीय कन्या आश्रम मोरडूंडिया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोरडूंडिया, शासकीय हाई स्कूल अंधारवड़ तथा माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर झांझरवा राणापुर का भ्रमण किया।

प्राथमिक विद्यालय खोकड़ी फलिया बन में विद्यार्थियों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम पाए जाने पर कलेक्टर ने संबंधित शिक्षकों को विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा अभिभावकों से सतत संपर्क स्थापित कर शत-प्रतिशत नामांकित विद्यार्थियों को विद्यालय से जोड़ने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर, झांझरवा में एक छात्रा को केवल आधार कार्ड अपडेट नहीं होने के कारण प्रोफाइल तैयार न होने से छात्रावास में प्रवेश नहीं दिए जाने की जानकारी मिली। इस पर कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी पात्र छात्रा की शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल छात्रा को छात्रावास में प्रवेश देने तथा आवश्यक दस्तावेजों की औपचारिकताएं नियमानुसार शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सभी विद्यालयों एवं छात्रावासों के प्रभारियों को निर्देशित किया कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण तथा सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता हो। उन्होंने कहा कि विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्राप्त हो सके। इस दौरान सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती सुप्रिया बिसेन एवं अन्य उपस्थित रहे।

वन स्टॉप सेंटर के परामर्श से ट्रॉमा से जूझ रहे दंपति का परिवार फिर से जुड़ा

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मानसिक आघात (ट्रॉमा) व्यक्ति के व्यवहार, सोच और पारिवारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। कई बार बचपन के दर्दनाक अनुभव जीवनभर व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, जिससे पारिवारिक जीवन भी संकट में पड़ जाता है। ऐसे ही एक परिवार को जिला मुख्यालय स्थित वन स्टॉप सेंटर, झाबुआ ने समय पर परामर्श एवं काउंसलिंग प्रदान कर पुनः साथ रहने के लिए प्रेरित किया।

वन स्टॉप सेंटर में एक महिला अपनी तीन माह की पुत्री एवं बहन के साथ सहायता के लिए पहुंची। महिला ने बताया कि उसके परिवार में ससुर, देवर, पति तथा तीन बेटियां हैं। सामान्य परिस्थितियों में पति का व्यवहार ठीक रहता है, लेकिन कई बार वह बिना किसी कारण महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच व्यक्त करने लगता है। वह महिलाओं के पहनावे, मोबाइल फोन के उपयोग, घर से बाहर जाने अथवा किसी पुरुष से बातचीत करने जैसी सामान्य बातों पर भी आपत्ति जताता था। इसी कारण पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद की स्थिति बन जाती थी। महिला ने बताया कि वह पिछले छह दिनों से अपनी बहन के घर रह रही थी, लेकिन इस दौरान पति ने उसका हालचाल तक नहीं पूछा।

प्रकरण प्राप्त होने पर वन स्टॉप सेंटर द्वारा महिला के पति को बुलाकर दोनों की विस्तृत काउंसलिंग की गई। परामर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि महिला का पति बचपन में हुए एक गंभीर मानसिक आघात (ट्रॉमा) से प्रभावित है। जब वह मात्र चार वर्ष का था, तब उसकी माता ने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया और उसे तथा उसके भाई-बहनों को असहाय स्थिति में छोड़ दिया।

दुग्ध क्रांति की ओर कदमः 10 हजार से ज्यादा पशुपालकों के घर पहुंची टीम, वैज्ञानिक पशुपालन का दे रही प्रशिक्षण

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जिले में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तृतीय चरण 13 से 17 जुलाई तक चलाया जा रहा है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान के तहत विभाग की टीमें पशुपालकों के घर-घर पहुंचकर उन्हें वैज्ञानिक पशुपालन की जानकारी दे रही हैं।

अभियान के अंतर्गत जिले के 10,084 ऐसे पशुपालकों को चिन्हित किया गया है, जिनके पास 3 से 4 गाय या भैंस हैं। प्रशिक्षित सर्वेयर और भेंटकर्ता निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उनके घर पहुंचकर पशु नस्ल सुधार, संतुलित आहार, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और आधुनिक वैज्ञानिक पशुपालन की तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं।

पशुपालकों को मध्यप्रदेश शासन के गोरस ऐप के उपयोग की जानकारी भी दी जा रही है, ताकि वे विभागीय योजनाओं और तकनीकी सलाह का लाभ आसानी से ले सकें। साथ ही वैज्ञानिक पशुपालन से जुड़ी चार जागरूकता रील भी उनके मोबाइल पर साझा की जा रही हैं।

विभाग के अनुसार 16 जुलाई तक 3,571 पशुपालकों के यहां गृह भेंट कर निर्धारित गतिविधियां पूरी की जा चुकी हैं। अभियान की गुणवत्ता और प्रगति पर जिला एवं विकासखंड स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन द्वारा नियमित समीक्षा और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के जरिए अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा रहा है।

नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0: नीमच पुलिस ने स्कूलों और फैक्ट्री में चलाया जागरूकता अभियान, दिलाई नशामुक्ति की शपथ

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा 15 से 30 जुलाई 2026 तक चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0 के तहत शुक्रवार को नीमच जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान का उद्देश्य युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना तथा नशामुक्त और स्वस्थ समाज के निर्माण में जनभागीदारी बढ़ाना है। पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास के निर्देशन में जिलेभर में लगातार जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

नीमच कैंट थाना क्षेत्र के सांदीपनि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नगर पुलिस अधीक्षक किरण चौहान एवं थाना प्रभारी सौरभ शर्मा ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को नशे से होने वाले सामाजिक, मानसिक और शारीरिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी। इस दौरान सभी विद्यार्थियों एवं स्कूल स्टाफ को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई और अपने परिवार व समाज को भी नशे के प्रति जागरूक करने का संकल्प कराया गया। वहीं जावद थाना क्षेत्र की बिरला सीमेंट फैक्ट्री, खोर में एसडीओपी हर्ष राठौर एवं थाना प्रभारी मनोज सिंह जादौन ने लगभग 300 फैक्ट्री कर्मचारियों को संबोधित करते हुए नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी और सभी को नशामुक्ति की शपथ दिलाई।

इसके अलावा जावद के शासकीय मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय, रतनगढ़ कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, पिपलिया घोटा शासकीय बालक हाई स्कूल तथा रामपुरा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में भी पुलिस अधिकारियों ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। विद्यार्थियों और शिक्षकों को नशे से दूर रहने तथा समाज में जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। पुलिस का कहना है कि नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0 स्वस्थ युवा, सुरक्षित समाज और सशक्त राष्ट्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है।

कलेक्टर ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मोरडूंडिया का किया निरीक्षण

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने आज एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मोरडूंडिया का निरीक्षण कर शैक्षणिक एवं आवासीय गतिविधियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने छात्रावास में विद्यार्थियों के साथ बैठकर भोजन किया तथा उनसे आत्मीय संवाद करते हुए उनकी दिनचर्या, अध्ययन और छात्रावास की सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं का भ्रमण कर विद्यार्थियों से पढ़ाई, विषयों की समझ एवं उनके भविष्य के लक्ष्यों के बारे में चर्चा की। उन्होंने बच्चों से बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, यह पूछा तथा उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत और अनुशासन के साथ अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, कंप्यूटर लैब, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी तथा मेडिकल रूम का भी निरीक्षण कर उपलब्ध व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।

विद्यार्थियों से कलेक्टर ने कहा कि धरती पर मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीक तेजी से विकसित हो रही है। इसलिए विद्यार्थियों को बदलती तकनीक के साथ स्वयं को भी निरंतर अपडेट रखना चाहिए तथा नई-नई चीजें सीखने की आदत विकसित करनी चाहिए।

कलेक्टर ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें और उसे प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा एवं समर्पण से प्रयास करें। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनने के लिए केवल पढ़ाई ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि छोटी-छोटी बातों का सूक्ष्म निरीक्षण और विश्लेषण करने की क्षमता भी आवश्यक होती है। एक चिकित्सक को रोगी की समस्या के पीछे के कारणों को समझकर सही उपचार करना होता है। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए जिज्ञासा, अवलोकन क्षमता और निरंतर सीखने की भावना आवश्यक है।

नशे से दूरी है जरूरी 2.0, सब जेल जावद में बंदियों से की नशामुक्ति जनजागरूकता

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नशे के विरूद व्यापक नशामुक्ति जनजागरूकता अभियान नशे से दुरी है जरूरी 2.0 15 जुलाई 2026 से 30 जुलाई 2026 तक सम्पूर्ण मध्यप्रदेश द्वारा चलाया जा रहा है। अभियान अंतर्गत आज दिनांक 15 जुलाई 2026 को नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत कलेक्टर महोदय श्री हिमांशु चन्द्रा के आदेशानुसार एवं जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सूश्री श्रुति भयडिया के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय विभाग एवं रेडक्रॉस नशा मुक्ति केंद्र नीमच के द्वारा सब जेल जावद में बंदियों के बीच नशामुक्ति परिचर्चा की गई।

परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य बंदियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना, उनकी इच्छाशक्ति को मजबूत करना और समाज में एक बेहतर नागरिक के रूप में लौटने के लिए प्रेरित करना है। जेलों में बंदियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधार के लिए नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया उक्त कार्यक्रम अंतर्गत कैदियों को अपराध की राह पर धकेलने वाले नशे के कुचक्र से बाहर निकालना और समाज की मुख्यधारा से जुडनें हेतु समझाया गया, बंदियों को समझाया गया कि नशा व्यक्ति को नहीं, बल्कि व्यक्ति नशे को पकड़ता है, मजबूत संकल्प से इसे आसानी से छोड़ा जा सकता है। साथ ही बंदियों को यह भी समझाया गया कि जेल से रिहा होने के बाद एक जिम्मेदार और ईमानदार नागरिक के रूप में समाज में लौटने की प्रेरणा दी गई राष्ट्रीय नशामुक्ति हेल्पलाईन नम्बर 14446 एवं मादक पदार्थो की तस्करी से राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाईन नम्बर MANAS-1933 का व्यापक पचार-प्रसार भी किया गया । उक्त कार्यक्रम में नशा मुक्ति केंद्र के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री सुनील तिवारी, मनोवैज्ञानिक श्री जीवन तिवारी, ए.ए. ग्रुप एवं जेल स्टॉफ के सदस्य एवं सब जेल विभाग के सदस्य उपस्थित रहें। कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सदस्?य उपस्थित थे।

वीएचएसएनडी एवं दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान का जिला टीकाकरण अधिकारी ने किया निरीक्षण

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले में संचालित वीएचएसएनडी (ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस) तथा दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शुक्रवार को जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. जी. एस. चौहान ने विकासखंड राणापुर अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टिकड़ी बोड़िया एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पाडलवा में आयोजित वीएचएसएनडी सत्रों एवं दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान का निरीक्षण किया। इस दौरान अभियान की मॉनिटरिंग ह्र्छ्य ञ्शश्द्य के माध्यम से की गई।

निरीक्षण के दौरान सत्र स्थलों पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, एएनएम, सहयोगिनी, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित पाए गए। सभी हितग्राही निर्धारित सूची के अनुसार सत्र में उपस्थित थे। डॉ. चौहान ने सत्र स्थलों पर नियमित टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तथा पोषण संबंधी गतिविधियों के संचालन का अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि निर्धारित माइक्रोप्लान के अनुरूप सभी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान के अंतर्गत पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की सक्रिय स्क्रीनिंग की गई। पात्र बच्चों को विटामिन-ए, आयरन सिरप, ओआरएस पैकेट एवं जिंक टैबलेट का वितरण किया गया। साथ ही बाल्यकालीन बीमारियों की पहचान कर गंभीर कुपोषित एवं गंभीर रूप से बीमार बच्चों को चिन्हित करते हुए आवश्यक रेफरल की कार्यवाही भी सुनिश्चित की गई।

निरीक्षण के दौरान जिला टीकाकरण अधिकारी ने स्वास्थ्य अमले को निर्देशित किया कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सभी हितग्राहियों की शत-प्रतिशत ऑनलाइन प्रविष्टि U-WIN Portal एवं अनमोल पोर्टल पर समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन DSS App के माध्यम से मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग अनिवार्य रूप से की जाए।

मानसून की लंबी खेंच के बीच किसानों को कृषि विभाग की महत्वपूर्ण सलाह

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले में मानसून के आगमन में हुई देरी तथा बारिश की लंबी खेंच (सूखे के अंतराल) को देखते हुए कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए समसामयिक तकनीकी सलाह जारी की गई है। उप संचालक कृषि श्री नगीन सिंह रावत ने किसानों से अपील की है कि वे वर्तमान परिस्थितियों में खड़ी फसलों को सुरक्षित रखने तथा भूमि में उपलब्ध नमी का अधिकतम संरक्षण करने के लिए वैज्ञानिक कृषि उपाय तत्काल अपनाएं, जिससे फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।

उप संचालक कृषि ने बताया कि भूमि की ऊपरी सतह में नमी बनाए रखने के लिए किसान अपने खेतों में शीघ्र निंदाई-गुड़ाई कराएं। इसके साथ ही खेतों में डोरा अथवा कुलपा अवश्य चलाएं। इससे मिट्टी की केशिकाएं (कैपिलरी) टूट जाती हैं और भूमि के भीतर उपलब्ध नमी का वाष्पीकरण कम होता है, जिससे फसल को अधिक समय तक नमी मिलती रहती है।

उन्होंने किसानों को खेतों में उगने वाले खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण करने की भी सलाह दी है। खरपतवार उपलब्ध नमी एवं पोषक तत्वों का अधिक उपयोग करते हैं, जिससे मुख्य फसल प्रभावित होती है। समय पर खरपतवार नियंत्रण करने से फसल को उपलब्ध नमी और पोषक तत्वों का पूरा लाभ मिल सकेगा।

जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए सीमित जल उपलब्ध है,उन्हें परंपरागत सिंचाई पद्धति के स्थान पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इन प्रणालियों से कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई संभव होती है तथा जल का दक्षतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित होता है।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे मौसम की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए अपनी फसलों की नियमित निगरानी करते रहें। यदि किसी प्रकार के कीट या रोग का प्रकोप दिखाई दे तो तत्काल अपने क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी अथवा कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर वैज्ञानिक सलाह प्राप्त करें। कृषि विभाग ने कहा है कि समय पर अपनाए गए ये सरल एवं वैज्ञानिक उपाय भूमि में नमी संरक्षण के साथ-साथ फसलों की बेहतर वृद्धि एवं उत्पादन बनाए रखने में सहायक सिद्ध होंगे। किसान भाई विभाग द्वारा समय-समय पर जारी तकनीकी सलाह का पालन कर अपनी फसलों को संभावित नुकसान से बचा सकते है।

अ.जा. आयोग के सदस्य रामलाल मालवीय ने आगर और नलखेड़ा के बालिका छात्रावासों का किया निरीक्षण

आगर-मालवा/दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री रामलाल मालवीय ने बालिका सीनियर छात्रावास क्रमांक-02 आगर एवं बालिका उत्कृष्ट छात्रावास नलखेड़ा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाओं, भोजन, स्वच्छता एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर श्री मालवीय ने छात्रावास परिसर में पौधारोपण भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवीन सत्र में छात्रावासों की 100 प्रतिशत सीटों पर विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। इस मौके पर जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग आगर, श्री शेखर उइके,डिप्टी कलेक्टर श्री कमल मंडलोई, उपस्थित थे।

संध्याकालीन शिविरों के दूसरे दिन 21 शिकायतें में से 7 का हुआ मौके पर ही निराकरण

आलोट/ राकेश चौहान/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के निर्देशानुसार जिले की समस्त 8 नगरीय निकायों में शुक्रवार को संध्याकालीन वार्ड स्तरीय शिविरों के द्वितीय चरण के दूसरे दिन जनप्रतिनिधियों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की उपस्थिति में शिविर आयोजित किए गए।

पीओ डूडा श्री अरुण कुमार पाठक द्वारा बताया गया कि नगर पालिका जावरा के वार्ड क्रमांक 5 एवं 6 तथा जिले की सातों नगर परिषदों के वार्ड क्रमांक 3 में आयोजित शिविरों में नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं। शिविरों में कुल 21 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 7 शिकायतों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया।

प्राप्त शिकायतों में 8 शिकायतें पेयजल से संबंधित थीं, जिनमें से 1 शिकायत का तत्काल निराकरण किया गया। 9 शिकायतें स्वच्छता संबंधी थीं, जिनमें से 6 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। इसके अतिरिक्त 4 शिकायतें निर्माण कार्यों से संबंधित प्राप्त हुईं, जिनके निराकरण के लिए संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई के निर्देश संबंधित कर्मचारियों को दिए गए।

शिविरों का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना तथा नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना है।

मालिक, प्रकाशक, मुद्रक विजय शर्मा द्वारा 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से प्रकाशित एवं भगवती ऑफसेट 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक - विजय शर्मा, मो.नं. 94250-22499, फोन 0734-2553435 प्रधान संपादक : शुभम ताम्रकार (सभी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा)

10 करोड़ का अंतरराष्ट्रीय स्वीमिंग पूल खेल विभाग को सौंपने की तैयारी

शासन से मंजूरी का इंतजार- एमआईसी से प्रस्ताव पास

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर निगम कार्यालय के पीछे स्थित अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्वीमिंग पूल को खेल विभाग को सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम की एमआईसी (महापौर परिषद) इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। अब अंतिम अनुमति के लिए प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा गया है। शासन से हरी झंडी मिलते ही स्वीमिंग पूल का संचालन, रखरखाव और भविष्य की पूरी जिम्मेदारी खेल विभाग के पास होगी।

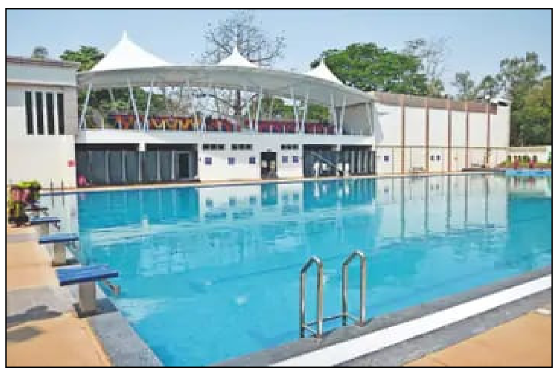

नगर निगम का कहना है कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य शहर के खिलाड़ियों और तैराकों को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। खेल विभाग के संचालन में आने के बाद पूल का उपयोग खेल गतिविधियों और प्रतिभाओं को निखारने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2019 में बने इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्वीमिंग पूल का शुरुआती संचालन नगर निगम ने किया था। हालांकि समय के साथ रखरखाव और संचालन में कई व्यावहारिक दिक्कतें सामने आईं। इसके बाद निगम ने निजी एजेंसी के माध्यम से संचालन कराने का निर्णय लिया। पिछले वर्ष टेंडर प्रक्रिया के बाद एक निजी कंपनी ने कुछ समय तक पूल का संचालन किया, लेकिन गर्मी के मौसम में भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने से यह व्यवस्था सफल नहीं हो सकी।

एमआईसी बैठक में हुई थी चर्चा- स्वीमिंग पूल को खेल विभाग को सौंपने का प्रस्ताव एमआईसी की बैठक में रखा गया था। शुरुआत में निगम की संपत्ति दूसरे विभाग को हस्तांतरित करने को लेकर कुछ सदस्यों ने सवाल उठाए थे। बाद में चर्चा के बाद अधिकांश सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई और इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया।

शासन स्तर पर प्रक्रिया जारी- नगर निगम के अपर आयुक्त संतोष टैगोर ने बताया कि प्रस्ताव पर शासन स्तर पर आगे की प्रक्रिया जारी है। जैसे ही अनुमति मिलेगी, खेल विभाग पूल का संचालन अपने हाथ में लेकर उसके उपयोग और भविष्य की कार्ययोजना तय करेगा। खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों का मानना है कि यदि स्वीमिंग पूल का संचालन खेल विभाग के माध्यम से नियमित और व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, तो उज्जैन में तैराकी को नई पहचान मिलेगी और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने में भी मदद मिलेगी।

गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ को लगाए 56 भोग

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। रथयात्रा के बाद अपनी मौसी गुंडीचा मंदिर पहुंचे भगवान जगन्नाथ की शुक्रवार सुबह मंगल आरती और दर्शन-पूजन किया गया। सुबह 8 बजे से कथा का आयोजन हुआ, जबकि शाम को भगवान को छप्पन भोग अर्पित किया गया। इसके साथ ही प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। श्रीकृष्ण पाथेय न्यास, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ और इस्कॉन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अमेरिका से आए जगदानंद प्रभुजी ने भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा भगवान श्रीकृष्ण को द्वारका से वृंदावन ले जाने की भावनात्मक लीला का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी की रथयात्रा में शामिल होते थे और आज भी उसी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। शाम को कृष्ण किशोर के प्रवचन हुए। इसके बाद कलाकारों द्वारा भक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुतियां दी गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए।

रथयात्रा में जेबकटी की आशंका पर 24 संदिग्ध पकड़े

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। इस्कॉन की भगवान जगन्नाथ रथयात्रा के दौरान जेबकटी और मोबाइल चोरी की आशंका पर पुलिस ने 24 संदिग्धों को हिरासत में लिया। कार्रवाई करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने 10 हजार रुपए के इनाम की घोषणा भी की। रथयात्रा गुरुवार को इंदिरानगर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से फ्रीगंज पहुंची थी। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भीड़ के बीच कुछ लोगों के संदिग्ध गतिविधियां करने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने उन्हें पकड़कर माधवनगर थाने पहुंचाया। शुक्रवार सुबह थाने में करीब 12 संदिग्ध मौजूद थे, जिनमें अधिकांश नाबालिग बताए गए। पुलिस के अनुसार अभी तक किसी के पास से चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ है। जिन लोगों ने जेबकटी या मोबाइल चोरी की शिकायत की है, उनके आवेदनों की जांच की जा रही है। सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया कि 24 संदिग्धों को थाने लाया गया था। इनमें से तीन लोगों पर धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। शिकायतों की जांच पूरी होने के बाद आवश्यक होने पर प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

म.प्र. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री धुर्वे द्वारा आज जिला स्तरीय बैठक ली जाएगी

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री मंगल सिंह धुर्वे के शुक्रवार 18 जुलाई को उज्जैन प्रवास के दौरान जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को दिए जा रहे लाभ तथा प्रचलित प्रकरणों की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी।

10 दिन से थमी बारिश, सोयाबीन की फसल पर संकट के बादल

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले में पिछले करीब 10 दिनों से बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खरीफ सीजन की प्रमुख फसल सोयाबीन पर इसका असर दिखाई देने लगा है। लगातार धूप निकलने और बारिश नहीं होने से खेतों की नमी तेजी से कम हो रही है। कई जगहों पर सोयाबीन के पौधे मुरझाने लगे हैं, जिससे किसानों को उत्पादन घटने की आशंका सता रही है। किसानों का कहना है कि इस समय सोयाबीन की फसल को पर्याप्त नमी की जरूरत होती है। बारिश रुकने से पौधों की बढ़वार प्रभावित हो रही है। यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो फसल को नुकसान हो सकता है। कई किसानों ने सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण प्राकृतिक बारिश पर ही भरोसा जताया है। कृषि विशेषज्ञों का भी मानना है कि सोयाबीन की अच्छी वृद्धि के लिए समय पर बारिश जरूरी है। यदि जल्द वर्षा होती है तो फसल को संभलने का मौका मिल सकता है। फिलहाल किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहे हैं।

3 साल में 20.92 करोड़ श्रद्धालुओं ने किए महाकाल के दर्शन

दान और लड्डू प्रसाद से मंदिर को 356 करोड़ की आय- गुप्त दान से भी पहली बार 4.65 करोड़ रुपए मिले

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। महाकालेश्वर मंदिर में पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था का नया रिकॉर्ड बना है। वर्ष 2023 से 2025 के बीच देश-विदेश से 20.92 करोड़ श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान मंदिर प्रबंध समिति को दान और लड्डू प्रसाद की बिक्री से कुल 356.17 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई। वहीं पहली बार गुप्त दान के रूप में भी 4.65 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।

मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक के अनुसार तीन वर्षों में श्रद्धालुओं से मिले दान का उपयोग मंदिर के विकास, निर्माण कार्यों और विस्तारीकरण में किया जा रहा है। यह कार्य सिंहस्थ-2028 की तैयारियों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वर्तमान में मंदिर प्रबंध समिति के खजाने में करीब 472 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में 5.30 करोड़ श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंचे थे, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर रिकॉर्ड 8.42 करोड़ तक पहुंच गई। लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मंदिर परिसर में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मंदिर की आय में 175.70 करोड़ रुपए दान के रूप में प्राप्त हुए, जबकि लड्डू प्रसाद की बिक्री से 180.77 करोड़ रुपए की आय हुई। इसके अलावा वर्ष 2025 में पहली बार श्रद्धालुओं ने गुप्त दान के रूप में 4.65 करोड़ रुपए अर्पित किए, जो मंदिर के लिए एक नई उपलब्धि मानी जा रही है। प्रशासक ने बताया कि वर्ष 2022 में महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले प्रतिदिन मंदिर में लगभग 40 से 50 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए आते थे। लेकिन 11 अक्टूबर 2022 को महाकाल लोक के शुभारंभ के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई और अब सामान्य दिनों में प्रतिदिन डेढ़ से दो लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं।

विशेष अवसरों पर यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है। महाशिवरात्रि, सावन-भादौ और नागपंचमी जैसे पर्वों पर एक दिन में 5 से 8 लाख श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं, जिससे उज्जैन देश के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्रों में शामिल हो गया है।

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर प्रबंध समिति सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत कई नई परियोजनाओं पर काम कर रही है। इसी क्रम में इंदौर-उज्जैन मार्ग पर 2200 कमरों का आधुनिक भक्त निवास बनाया जा रहा है, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर आवास सुविधा मिल सके। साथ ही मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भी सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है।

अवैध शराब के साथ पकड़ाये बदमाशों ने काबुली भैंस चोरी की वारदात

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। रात के अंधेरे में बिना नम्बर की पिकअप से अवैध शराब का परिवहन होने की खबर मिलने पर पुलिस ने नाकाबंदी की। पिकअप को रोकने पर उसमें कच्ची शराब से भरी केन मिली। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। दोनों ने पूछताछ में भैंस चोरी की वारदात भी कबूल की है। महिदपुर थाना प्रभारी अशोक कुमार पाटीदार ने बताया कि बुधवार-गुरूवार रात खबर मिली थी कि बिना नम्बर की पिकअप में अवैध शराब का परिवहन हो रहा है। सूचना पर रसूलपुरा फंटा पर नाकाबंदी की गई। बिना नम्बर की पिकअप आने पर रोका गया, उसमें 2 व्यक्ति सवार थे, दोनों को हिरासत में लिया गया और पिकअप की तलाशी ली गई। उसमें 30 लीटर कच्ची शराब से भरी केन बरामद हो गई। दोनों को थाने लाया गया और पूछताछ शुरू की गई। उनके नाम सुरेश गायरी निवासी खासपुरा आलोट और धीरब कंजर निवासी अरनिया डेरा सामने आये। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 49-ए का प्रकरण दर्ज कर 5 लाख कीमत की पिकअप जप्त की गई। दोनों को गुरूवार दोपहर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पूछताछ के लिये रिमांड पर लिया गया है। दोनों से अवैध शराब के स्त्रोत और अवैध कारोबार में शामिल साथियों की जानकारी जुटाई जा रही थी, इस दौरान उनसे भैंस चोरी की वारदात का भी खुलासा हो गया। थाना प्रभारी के अनुसार दोनों बदमाशों ने 14-15 जुलाई की रात महिदपुर के रहने वाले संजय बगाना के खेत से भैंस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था दोनों के निशान देही पर चोरी की 2 भैंस बरामद की गई है।

बुजुर्ग मां घर लौटी तो फंदे पर लटका मिला पुत्र

उज्जैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। पारिवारिक विवाद के चलते कुछ दिन पहले पत्नी बच्चे ड्राइवर को छोड़कर चले गए थे वापस नहीं आने पर ड्राइवर ने फांसी लगा ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पंवासा थाना पुलिस ने बताया कि जुनी ताजपुर में रहने वाली बुजुर्ग धापू बाई सोलंकी ने आसपास के लोगों की मदद से सूचना दी की उसके 52 वर्षीय पुत्र राजाराम पिता कालूराम सोलंकी ने घर में रस्सी का फंदा गले में डालकर फांसी लगा ली है। पुलिस घटना स्थल पहुंची और शव को नीचे उतारा गया। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के दौरान सामने आया कि राजाराम ड्राइवरी करता था और शराब पीने का आदी था। जिसके चलते एक माह पहले पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए थे। संभवत इसी वियोग में उसने फांसी लगाई है वह अपनी बुजुर्ग मां के साथ अकेला रहता था। परिजनों का कहना था कि राजाराम के फांसी लगाने की खबर मिलने पर पत्नी और बच्चे लौट आए हैं।

भागकर प्रेम विवाह करने वाले युवक के साथ मारपीट

उज्जैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। प्रेम विवाह करने वाले युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। युवक को उसकी प्रेमिका के भाई और रिश्तेदारों ने बुरी तरह पीटा। युवक को उपचार के लिए उज्जैन लाया गया है।

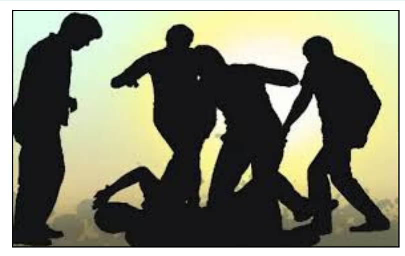

अस्पताल में भर्ती तराना तहसील के ग्राम करंज के रहने वाले लक्ष्मण पिता राजाराम 24 साल ने बताया कि दो माह पहले उसने सतीश नामक युवक के मामा की लड़की से प्रेम विवाह किया था। प्रेमिका के साथ वह बड़ोद चला गया था। कुछ दिन बाद प्रेमिका के परिजन उसे समझ कर अपने साथ ले गए थे। उसे पर दबाव बनाया जा रहा था जिसके चलते प्रेमी का वापस उसके पास आ गई थी और दोनों ग्राम करंज में रहने लगे थे। गुरुवार को प्रेमिका के मां का लड़का सतीश अपने रिश्तेदार भोला, मुकेश, धर्मेंद्र और 8-10 अन्य के साथ आया। सभी ने घेर कर उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की है। घायल होने पर परिजन उसे उपचार के लिए उज्जैन लेकर आए हैं। मामले की जांच तराना पुलिस द्वारा घायल के बयान दर्ज कर की जाएगी।

हाईटेंशन से टकराई जेसीबी एक की मौत, दो झुलसे

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। सरपंच पति की शिकायत पर जेसीबी से गुमटी हटाने पहुंचे चालक और उसके दो साथियों के साथ हादसा हो गया गुमटी उठाते समय हाई टेंशन लाइन से करंट लगा और चालक की मौत हो गई उसके दो साथी झुलस गए। शुक्रवार सुबह मृतक चालक का पोस्टमार्टम कराया गया। इंगोरिया से रात में संदीप पिता मेहरबान भाटी 30 साल और उसके दो साथी दिनेश और मेहरबान को चरक अस्पताल लाया गया था। संदीप की मौत हो चुकी थी दिनेश और मेहरबान को उपचार के लिए भर्ती किया गया। तीनों को करंट लगा था। संगीत की मौत होने पर अस्पताल पुलिस चौकी द्वारा मर्ग कायम किया गया आज सुबह पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों ने बताया कि संदीप तीन बच्चों का पिता था और जेसीबी डंपर चलता था। जेसीबी उसकी थी, रात में सरपंच पति नरेंद्र ने गांव में एक गुमटी हटाने के लिए बुलाया लेकिन दो मजदूरों की जरूरत थी जिसके चलते संदीप अपने दो साथी दिनेश और मेहरबान को लेकर पहुंचा था। गुमटी उठाते समय ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टकरा गई इसके चलते करंट फैला था। अस्पताल पुलिस चौकी के अनुसार मामला इंगोरिया थाना क्षेत्र का है घटना की जांच संबंधित पुलिस द्वारा की जाएगी। ग्राम नाग गुराडिया से 17 वर्षीय कुमारी राधा पिता दशरथ सूर्यवंशी को जहरीला पदार्थ खाने के बाद परिजन उज्जैन लेकर पहुंचे थे। निजी अस्पताल में उपचार के दौरान रात को राधा की मौत हो गई। सूचना मिलने पर माधव नगर थाना पुलिस निजी अस्पताल पहुंची और मृतक राधा का शव पोस्टमार्टम के लिए चरक अस्पताल लाया गया। राधा ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया इसकी वजह सामने नहीं आ पाई है।

सिंहस्थ 2028 के निर्माण कार्यों में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

आईआईटी मुंबई के विशेषज्ञों ने दिया व्यावहारिक प्रशिक्षण, लाइव डेमो एवं गतिविधियों के माध्यम से सिखाएं सुरक्षा मानक

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से सिंहस्थ मेला अधिकारी एवं संभागायुक्त श्री आशीष सिंह तथा कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह के मार्गदर्शन में किए जा रहे नवाचारों की श्रृंखला के अंतर्गत ÷कंस्ट्रक्शन सेफ्टी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम÷ का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए लोक निर्माण विभाग (सेतु संभाग), उज्जैन को नोडल एजेंसी नामित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिंहस्थ 2028 से संबंधित विभिन्न निर्माण एवं अधोसंरचना कार्यों में संलग्न अधिकारियों एवं अभियंताओं को आधुनिक निर्माण सुरक्षा मानकों, कार्यस्थल सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली तथा सुरक्षित निर्माण प्रक्रियाओं के संबंध में प्रशिक्षित करना था, ताकि निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग, एमपीआरडीसी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग सहित विभिन्न विभागों के अभियंताओं एवं तकनीकी अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की विशेषता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मुंबई के विषय विशेषज्ञों द्वारा आयोजित अत्यंत सहभागितापूर्ण एवं व्यावहारिक सत्र रहे। विशेषज्ञों ने निर्माण सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर लाइव डेमो प्रस्तुत कर प्रतिभागियों को सुरक्षा उपकरणों के सही उपयोग, संभावित जोखिमों की पहचान तथा दुर्घटना निवारण के उपायों की जानकारी दी। प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिभागियों को विभिन्न समूह गतिविधियों एवं व्यवहारिक अभ्यासों में सम्मिलित किया गया, जिससे अधिकारियों एवं अभियंताओं को निर्माण स्थलों पर सुरक्षा प्रबंधन की प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से समझने एवं व्यवहार में अपनाने का अवसर प्राप्त हुआ।

प्रशिक्षण के दौरान आईआईटी मुंबई के विशेषज्ञों ने निर्माण स्थलों का निरीक्षण भी किया तथा मौके पर ही सुरक्षा मानकों, संभावित जोखिमों एवं उनके प्रभावी निराकरण के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया।

जिला कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने प्रशिक्षण में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं अभियंताओं को निर्देशित किया कि वे प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान का पूर्ण लाभ उठाते हुए इसे एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में अपने-अपने निर्माण स्थलों पर लागू करें। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ 2028 से संबंधित प्रत्येक निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ-साथ सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में, उत्कृष्ट गुणवत्ता एवं उच्चतम सुरक्षा मानकों के अनुरूप पूर्ण हों, जिससे श्रमिकों, अधिकारियों तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सके।

कलेक्टर श्री सिंह के मार्गदर्शन में जिले में प्राकृतिक खेती को मिल रहा बढ़ावा

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जिले में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को विकासखंड खाचरौद के ग्राम घिनौदा में प्राकृतिक खेती का अवलोकन किया गया तथा प्राकृतिक खेती अपनाने वाले प्रगतिशील कृषक श्री गिरधारीलाल पाटीदार की नवनिर्मित गौशाला का उद्घाटन एवं पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में परियोजना संचालक (पीडी) आत्मा श्री के.एस. केन, सहायक संचालक कृषि श्री कमलेश कुमार राठौर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री संदीप करोड़िया एवं कृषि विभाग की टीम उपस्थित रही। अधिकारियों ने श्री गिरधारीलाल पाटीदार के फार्म का निरीक्षण कर प्राकृतिक खेती एवं गौ-आधारित कृषि को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों की सराहना की।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने फार्म पर पौधरोपण भी किया। श्री पाटीदार द्वारा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत मूंगफली, रेज्ड बेड पद्धति पर मक्का तथा सफेद मूसली की खेती की जा रही है। साथ ही प्राकृतिक खेती के प्रमुख घटक जीवामृत, घनजीवामृत, पाँच पत्ती अर्क सहित अन्य जैविक आदानों का निर्माण भी फार्म पर किया जा रहा है।

इस अवसर पर उपस्थित किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती के लाभों की विस्तृत जानकारी देते हुए अधिकारियों ने सलाह दी कि किसान प्रारंभ में स्वयं के उपयोग हेतु प्राकृतिक खेती अपनाएं और धीरे-धीरे इसका क्षेत्रफल बढ़ाएं। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन लागत में कमी आती है, मिट्टी की उर्वरता एवं जैव विविधता बढ़ती है तथा सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न का उत्पादन संभव होता है।

गिरफ्त में आया कातिलाना हमला करने वाला आरोपी

उज्जैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। बिरलाग्राम थाना क्षेत्र के विद्यानगर में 14 जुलाई को रात 11 बजे संतोष पिता रामसिंह निषाद 38 साल घर लौट रहा था। उसी दौरान विद्यानगर में रहने वाले बलराम पिता मोहनलाल ने पुरानी रंजीश में संतोष का रास्ता रोक कातिलाना हमला कर दिया था। हमलावर ने बाल काटने के उस्तरे से गले पर वार किया था। घटनाक्रम देख आसपास के लोग बीच-बचाव करने पहुंचे थे, इस दौरान बलराम ने उन्हे भी जान से मारने की धमकी दी थी और भाग निकला था। गंभीर घायल संतोष को उपचार के लिये नागदा जनसेवा अस्पताल भेजा गया था, मामले में घायल के रिश्तेदार पूनम साहनी की शिकायत पर हमलावर के खिलाफ कातिलाना हमले की धारा 109(1), 296 (अ), 351(3) बीएनएस का प्रकरण दर्ज किया था। थाना प्रभारी जितेन्द्र पाटीदार ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिये एसआई संजय माथुर, शांतिलाल मौर्य, एएसआई दयाशंकर, प्रधान आरक्षक नरेंद्र, संग्राम, आरक्षक संदीप यादव, नटवर सिंह की टीम बनाई गई और उसके ठिकानों का पता लगाकर दबिश दी गई। 36 घंटे बाद हमलावर बलराम हिरासत में आ गया। उसकी निशानदेही पर उस्तरा और ब्लेड़ बरामद की गई है। आरोपी को गुरूवार दोपहर न्यायालय में पेश किया था, जहां से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के विद्यार्थियों को सिंहस्थ-2028 से जुड़े निर्माण कार्यों का भ्रमण कराया जाए

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, उज्जैन की शासी निकाय की 34वीं बैठक प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में महाविद्यालय के समग्र विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं व्यावहारिक कौशल को सुदृढ़ बनाने से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में आगामी शैक्षणिक एवं विकासात्मक गतिविधियों के लिए प्रस्तुत बजट प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया, जिन्हें सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने विभिन्न प्रस्तावों पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए तथा कुछ विषयों पर आवश्यक आपत्तियां एवं सुधार संबंधी निर्देश भी प्रदान किए।

कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि महाविद्यालय परिसर में प्रस्तावित बाउंड्री वॉल निर्माण के संबंध में स्वयं स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। कलेक्टर ने पुराने एवं अनुपयोगी घोषित कन्या छात्रावास के संबंध में सक्षम अधिकारियों से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विद्यार्थियों को व्यवहारिक एवं तकनीकी अनुभव प्रदान करने पर बल देते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को वर्तमान में संचालित सिंहस्थ-2028 से जुड़े निर्माण कार्यों का भ्रमण कराया जाए तथा उन परियोजनाओं पर आधारित तकनीकी प्रोजेक्ट तैयार करवाए जाएं। उन्होंने विद्यार्थियों को सिंहस्थ निर्माण कार्यों से जुड़ी कंसल्टेंसी संस्थाओं में प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास करने के भी निर्देश दिए। आधुनिक तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने अध्यापन एवं अध्ययन प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही, ताकि विद्यार्थी बदलते तकनीकी परिवेश के अनुरूप दक्ष बन सकें।

इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आर.सी. गुप्ता, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हढ्ढझ्ञ्झ्ञ्झ्ञ्ञ्क इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन शासी निकाय के सदस्य, पालक प्रतिनिधि, आरक्षित वर्ग प्रतिनिधि सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।